

मुकदमों का विवरण

BATLIBOI पर्यावरण इंजीनियर लिमिटेड v.

हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम सीमित और एक और

(सिविल अपील सं. 2012 का 1968) 21 सितंबर, 2023

[संजीव खन्ना और एम. एम. सुंदरेश, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ को प्रतिवादियों के नेतृत्व में अपील की अनुमति देने में न्यायसंगत ठहराया गया था। 37 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और इस प्रकार मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करना।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -धारा 37-माध्यस्थम् अधिनिर्णय-हस्तक्षेप के साथ-प्रत्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किए जाने वाले अनुबंध मूल्य के लिए अपीलार्थी को मुख्य अनुबंध का अधिनिर्णय-परियोजना को पूरा करने में देरी, जिसे बढ़ाया गया था, और उसके बाद अपीलार्थी ने काम छोड़ दिया, केवल 80 प्रतिशत काम पूरा हुआ-मामला मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ा-मध्यस्थता पुरस्कार ने प्रत्यर्थी के परिसमापन हर्जाने के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि विलंब प्रत्यर्थी की चूक और आयोगों के कारण हुआ था और इसके अन्य दावे को भी खारिज कर दिया गया था क्योंकि वे भविष्य के कार्यों से संबंधित थे-मध्यस्थता पुरस्कार को दरकिनार करते हुए डिवीजन बेंच द्वारा फिर से अनुमति दी गई अपील-न्यायनिर्णय:

आयोजित किया गया:गणना परिचर तथ्यों और परिस्थितियों और नुकसान की गणना करने के तरीकों पर निर्भर करती है-मात्रा का निर्धारण एक ऐसा मामला है जो मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र और निर्णय के भीतर आता है-हालाँकि, नुकसान की गणना सनकी और बेतुकी नहीं होनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप एक पक्ष के लिए दूसरे की कीमत पर अप्रत्याशित और इनाम होना चाहिए-नुकसान की गणना कपटपूर्ण नहीं होनी चाहिए-नुकसान को हुए नुकसान के अनुरूप होना चाहिए-मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पूरी तरह से अनुमति दी 442

441

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, आवश्यक देखभाल और सावधानी की अनदेखी की गई और एक तरफा दृष्टिकोण अपनाया, नुकसान को पूरी तरह से और असामान्य रूप से बढ़ाया-नुकसान की गणना के लिए कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया है या व्याख्या की जा सकती है-भले ही किसी को अपीलकर्ता द्वारा दिए गए चार्ट पर भरोसा करना पड़े, और फाइंडिंग में विरोधाभासों को नजरअंदाज करना पड़े, लेकिन प्रदान की गई राशि अत्यधिक असमान और अत्यधिक है-पेटेंट और अवैधताएं पुरस्कार से निकलती हैं, जैसे निष्कर्ष पर पहुंचने में तर्क की स्पष्ट कमी और दी गई राशि की गणना, जो वास्तव में, विरोधाभासी होने के अलावा, दोगुना या आंशिक-दोहरा भुगतान के बराबर है-इस प्रकार, पुरस्कार को उचित रूप से अस्थिर माना जाता है। 37 आरडब्ल्यू एस। 34. [पैरा 15,16,27 और 45]

एस. 34 - पुरस्कार के बाद हस्तक्षेप-न्यायालय की शक्ति का दायरा और परिधि:

आयोजित किया गया:मध्यस्थता की नींव पक्ष की स्वायत्तता है-पार्टियों को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपने विवादों/दावों को निपटाने के लिए एक समझौते में प्रवेश करने की स्वतंत्रता है, जिसका निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी है-अदालत को अपनी शक्तियों का प्रयोग तब करना चाहिए जब पुरस्कार अनुचित, मनमाना, विकृत या अन्यथा कानून में असंवैधानिक हो-जबकि मध्यस्थता विवाद समाधान का एक निजी रूप है, मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन को उचित प्रक्रिया और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और तर्कसंगतता की न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, ताकि 'न्यायिक रूप से' ध्वनि और उद्देश्यपूर्ण परिणाम प्राप्त किया जा सके-यदि ये आवश्यकताएं, जो मध्यस्थता सहित सभी प्रकार के निर्णयों के लिए समान रूप से मौलिक हैं, पर्याप्त नहीं हैं और परिणाम बाधित हैं, तो पुरस्कार को मध्यस्थता कार्यवाही में पर्याप्त रूप से समायोजित नहीं किया जाना चाहिए। [पैरा 31 और 32]

अनुबंध-नुकसान की गणना-इसके लिए विधि-अधिभार और लाभ के नुकसान का पता लगाने के लिए हडसन, एमडेन या आइकले जैसे सूत्रों का उपयोग करना:

आयोजित किया गया:तीन सूत्र सैद्धांतिक गणितीय समीकरणों से संबंधित हैं, लेकिन वे तथ्यात्मक मान्यताओं पर आधारित हैं, और इस प्रकार, तीन अलग-अलग और असंबंधित मुआवजे/नुकसान का उत्पादन कर सकते हैं-इस प्रकार, एक विशेष समीकरण या विधि को लागू करते समय, मान्यताओं की जांच की जानी चाहिए, और धारणाओं की संतुष्टि तथ्यों और परिस्थितियों में सुनिश्चित की जानी चाहिए-अन्य सूत्रों की तरह हडसन का सूत्र, जो कि अवशोषित ओवरहेड के लागत प्रभाव के केवल मोटे अनुमान हैं, को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण गणना सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी और सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए।धारा 34-443 तक सार्वजनिक नीति परीक्षण

बैटलिबॉय एनवायरनमेंटल इंजीनियर्स लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

एक मध्यस्थ पुरस्कार-अभिव्यक्ति 'सार्वजनिक नीति' यू/एस।34 - व्याख्या-स्पष्ट।[पैरा 21,25 और 38]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. बनामबर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड और

अन्य (2006) 11 एस. सी. सी. 181:[2006] 2 पूरक।एससीआर 409; एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (2015) 3 एससीसी 49:[2014] 13 एससीआर 895; ए. टी.

बृज पाल सिंह और अन्य बनाम गुजरात राज्य (1984) 4 एस. सी. सी. 59; विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा व्यापार निगम और अन्य, (2021) 2 एस. सी. सी. 1:[2020] 11 एससीआर 1001; ओएनजीसी लिमिटेड।v. सॉ पाइप्स लिमिटेड।(2003) 5 एससीसी 705:[2003] 3 एस. सी. आर. 691; हिन्दुस्तान जैंक लिमिटेड बनाम.मित्रों कोयला कार्बनीकरण (2006) 4 एस. सी. सी. 445; सेंट्रोटेड मिनरल्स एंड मेटल्स इंक. बनाम.हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (2006) 11 एससीसी 245; दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम आर. एस.

शर्मा एंड कंपनी (2008) 13 एस. सी. सी. 80:[2008] 12 एससीआर 785; जे. जी. इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड बनामभारत संघ और एक अन्य (2011) 5 एस. सी. सी. 758:[2011] 8 एससीआर 486; भारत संघ बनाम एल. एस. एन. मूर्ति (2012) 1 एस. सी. सी. 718:[2011] 13 एससीआर 295;

रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 1994 सप्लीमेंट (1) एससीसी 644:[1993] 3 पूरक।एस. सी. आर. 22; राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम.दीवान चंद

राम सरन (2012) 5 एस. सी. सी. 303:[2012] 4 एस. सी. आर. 1; ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनामवेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263:[2014] 12 एस. सी. आर. 1; उत्पाद शुल्क और कराधान

आधिकारिक सह-निर्धारण प्राधिकरण बनाम गोपी नाथ एंड संस 1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 312; कुलदिप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त (1999) 2 एस. सी. सी. 10:[1998] 3

पूरक।एससीआर 594; एम. एम. टी. सी. लिमिटेड बनाम.वेदांत लिमिटेड (2019) 4 एस. सी. सी. 163:[2019] 3

एस. सी. आर. 1023; सांगर्योंग एंग।& कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड बनामराष्ट्रीय राजमार्ग

भारतीय प्राधिकरण (2019) 15 एससीसी 131:[2019] 7 एस. सी. आर. 522-संदर्भित।

रॉबिन्सन बनाम हरमन (1848) 1 पूर्व 850 855 पर; लिविंगस्टोन बनाम रॉयाडर्स

कोल कंपनी (1879-80) एल. आर. 5880 मामले 25; पीक कंस्ट्रक्शन (लिवरपूल) लिमिटेड

वि. मैककिनी फाउंडेशन लिमिटेड (1970) 1 बीएलआर 114; व्हिटल बिल्डर्स बनाम चेस्टरले-स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (1987) 40 बीएलआर 82; जेएफ फिनेगन लिमिटेड बनाम शेफी एल्ड सिटी काउंसिल (1988) 43 बीएलआर 124; एलिस-डॉन बनाम टोरंटो पार्किंग प्राधिकरण (1978) 28 बीएलआर 98; प्रॉपर्टी एंड लैंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड बनाम अल्फ्रेड मैकएल्पाइन होम्स नॉर्थ लिमिटेड (1995) 76 बीएलआर 59; एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड (1987)

वि.वेड्सबरी निगम।, (1948) 1 के बी 223:(1947) 2 सभी ईआर 680 (सीए); आइकले निगम मामला, एएसबीसीए सं. 5183,60-2

बी. सी. ए-संदर्भित।

444 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील्य क्षेत्राधिकार:2012 की सिविल अपील No.1968।1999 के ए. पी. No.280 में 2001 के ए. एन. No.227 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 02.11.2007 से।

रूप:

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमर दवे, महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, आदिल परसुरामपुरिया, सुश्री एस. लक्ष्मी अय्यर, सुश्री तन्वी मनचंदा, निशांत राव, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, सूर्य प्रकाश, अर्जुन भाटिया, सुश्री अक्षता जोशी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

संजीव खन्ना, जे।

बटलीबोई एनवायरनमेंटल इंजीनियर्स लिमिटेड 1 द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दिनांकित 02.11.2007 के फैसले पर आपत्ति उठाती है, जिसके तहत बॉम्बे में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 4 की धारा 37 के तहत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3 के नेतृत्व में अपील 2 FI की अनुमति दी, और इस तरह दिनांकित 23.03.1999 के मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द कर दिया।

2. निविदा की स्वीकृति पर और दिनांक आई. डी. 1 के आशय पत्र के संदर्भ में, एच. पी. सी. एल. ने बी. ई. ई. एल. को माहुल रिफाइनरी क्षेत्र में 23 एम. एल. डी. क्षमता वाले सीवेज जल सुधार संयंत्र के सिविल और संरचनात्मक डिजाइन, आपूर्ति और निर्माण, परीक्षण और चालू करने सहित विस्तृत इंजीनियरिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुबंध प्रदान किया था।अनुबंध का मूल्य रु। 574.35 लाख।अनुबंध की अवधि आशय पत्र की तारीख से 18 महीने थी, और तदनुसार

1 संक्षेप में, बीईएल।

2 1999 की मध्यस्थता याचिका संख्या 280 में 2001 की अपील संख्या 227। 3 संक्षेप में, एचपीसीएल।

4 संक्षेप में, ए एंड सी अधिनियम।

445

BATLIBOI पर्यावरण इंजीनियर लिमिटेड बनाम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. [संजीव खन्ना, जे.] 446 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

28.08.1993 द्वारा कार्य पूरा किया जाना था।पूरा करने में देरी हुई।बी. ई. ई. एल. द्वारा किए गए लिखित अनुरोधों/आवेदनों पर, पूरा करने का समय दो मौकों पर बढ़ाया गया था।एच. पी. सी. एल. द्वारा तीन संशोधन भी जारी किए गए। अंतिम संशोधन दिनांक 20.09.1994 ने 26.09.1994 से पूरा करने की अवधि को 10 महीने के लिए बढ़ा दिया था, जिस तारीख को एचपीसीएल द्वारा विद्युत वस्तुओं की मंजूरी दी गई थी। बी. ई. ई. एल. ने आई. डी. 1 तक काम जारी रखा।इसके बाद बी. ई. ई. एल. ने काम छोड़ दिया।यह एक स्वीकृत स्थिति है कि 30.03.1996 पर 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया था।

3. 04.07.1996 पर, बी. ई. ई. एल. ने एच. पी. सी. एल. को निष्पादन में देरी के कारण अनुबंध के उल्लंघन के लिए एक औपचारिक दावा किया, जिससे अतिरिक्त खर्च और नुकसान हुआ।दिनांकित 16.05.1997 पत्र द्वारा, बी. ई. ई. एल. ने उन्हें काम फिर से शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए Rs.50 लाख का अग्रिम भुगतान करने की मांग की, और साथ ही सुलह के माध्यम से विवाद को हल करने की अपनी इच्छा व्यक्त की।उसी पत्र द्वारा बी. ई. ई. एल. ने अनुबंध में मध्यस्थता खंड का भी

आह्वान किया, यदि बी. ई. ई. एल. द्वारा दिया गया प्रस्ताव एच. पी. सी. एल. को अस्वीकार्य था। एच. पी. सी. एल. ने दिनांक 1 के पत्र द्वारा भुगतान करने से इनकार कर दिया, और अनुबंध की शर्तों पर भरोसा करते हुए बी. ई. ई. एल. को शेष काम को फिर से शुरू करने और पूरा करने के लिए प्रभावित किया, भले ही मामला मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ना हो। बी. ई. ई. एल. सहमत नहीं हुआ और काम फिर से शुरू कर दिया।

4. महाप्रबंधक (परियोजना), माहुल रेफी नेरी, एच. पी. सी. एल. ने श्री के. नारायणन को अनुबंध के निष्पादन में विवादों और विभिन्न त्रुटियों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। दावा बी. ई. ई. एल. के नेतृत्व में किया गया था और जवाब/जवाबी दावा एच. पी. सी. एल. के नेतृत्व में किया गया था, जिसके लिए सहायक दस्तावेजों और जवाबी-जवाब के साथ जवाब दिया गया था। 12.03.1998 और 07.01.1999 अवधि के बीच मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष कुल मिलाकर लगभग 14 सुनवाई आयोजित की गईं और मौखिक तर्कों को संबोधित किया गया। नेत्र साक्ष्य का नेतृत्व नहीं किया गया था। विद्वान मध्यस्थ ने 24.12.1997 पर स्थल निरीक्षण किया था।

5. दिनांकित 23.03.1999 का मध्यस्थ निर्णय, बी. ई. ई. एल. के दावे संख्या 1, 2 और 4 को काफी हद तक अनुमति देता है। बी. ई. ई. एल. के दावों से संबंधित पुरस्कार के प्रासंगिक भाग में लिखा है:

“उ. दावेदारों के दावे:

दावा संख्या 1-लाभ और लाभ के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति और लाभप्रदता भी:रुपये. **3,38,38,460.00**

दावा ओवरहेड्स और लाभ/लाभ योग्यता की अग्रिम हानि है जिसकी गणना 27.08.1997 के रूप में 48 महीने की देरी के आधार पर की जाती है। दावेदारों ने अपने द्वारा पहले से प्राप्त भुगतानों के समान प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त शुल्क पर पहुंचने के लिए अधिभार के लिए अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत और लाभ/लाभप्रदता के लिए अन्य 10 प्रतिशत पर विचार किया है।

मेरा उद्देश्य यह है कि 18 महीनों की दी गई अवधि में परियोजना को पूरा करने के रास्ते में आने वाली विभिन्न बाधाओं और बाधाओं को दूर करने में उचित और समय पर कार्रवाई नहीं करने से हुई भारी देरी के लिए मालिक उत्तरदाता पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। पार्टी को एक परियोजना से जोड़ा गया था, जिसे बिना किसी उद्देश्य के आगे बढ़ने दिया गया था, जिसमें मालिक-उत्तरदाताओं ने इसे समय पर पूरा करने में शायद ही कोई रुचि दिखाई थी।

यहां तक कि कई संशोधनों के साथ विद्युत योजना के लिए बुनियादी मंजूरी को भी बिना किसी निर्णय के अंत तक लंबित रखा गया था। दावेदार इन मंजूरी के बिना परियोजना को पूरा करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। इस प्रकार उत्तरदाताओं ने अपनी जिम्मेदारियों से बचने और संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन किया है। जैसा कि उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है, यहां तक कि शुद्धिकरण के लिए सीवेज पानी की आपूर्ति के लिए एम. सी. जी. बी. के साथ व्यवस्था को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उत्तरदाताओं की सलाह के अनुसार, यह मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा कर रहा है। यह किसी भी निकाय का अनुमान है कि इस व्यवस्था को कब आवश्यक पंपिंग स्टेशन और भूमिगत पाइपलाइनों आदि को तैयार किया जाएगा ताकि दावेदार द्वारा शुद्धिकरण के लिए बनाए जा रहे संयंत्र के कारण सीवेज का पानी निकल जाए। यह इस बात का प्रमाण है कि उत्तरदाता परियोजना को लागू करने में पर्याप्त गंभीर नहीं थे।

ऊपर दिए गए कारणों से, मेरा मानना है कि दावेदार कानूनी रूप से ओवरहेड के नुकसान और लाभ/लाभ योग्यता दोनों के लिए मुआवजे के हकदार हैं। मुआवजे पर पहुंचने के लिए, 30.03.1996 तक की अवधि पर विचार किया जा रहा है, जब दावेदारों ने काम बंद कर दिया था। कुल अवधि 49 महीने तक होती है। मूल अनुबंध अवधि 18 महीने है, विस्तारित अवधि 31 महीने तक आती है। दावेदारों ने अपने दावे के बयान में कहा था कि उन्होंने अपने अनुमान में 22 महीने के ओवरहेड का प्रावधान किया था। मैं मालिक की आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए 3 महीने की अनुमति दे रहा हूँ-447

BATLIBOI पर्यावरण इंजीनियर लिमिटेड बनाम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड. [संजीव खन्ना, जे.] 448 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

उत्तरदाताओं और अप्रत्याशित देरी जैसे हड़ताल, रेड अलर्ट आदि के लिए। मैं अधिभार के नुकसान के लिए अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत और लाभ/लाभप्रदता के नुकसान के लिए 10 प्रतिशत को भी उचित मानता हूँ। इन (एस. आई. सी.) आधार पर,

अधिभार के नुकसान के लिए Rs.78,68,833.00 और लाभ/लाभप्रदता के नुकसान के लिए Rs.78,68,833.00 की समान राशि, कुल रु. 1,57,37,666.00 उनके द्वारा किए गए काम के लिए पहले से प्राप्त भुगतानों से समान प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए। मैं यह राशि दावेदारों को देता हूँ।

उपरोक्त क्षतिपूर्ति प्रदान करते समय, नुकसान को कम करने के साधनों के अस्तित्व पर विचार किया गया है। मेरे अनुसार, दावेदारों के लिए उपलब्ध एकमात्र साधन रविवार और छुट्टियों पर काम करना था, ताकि कुछ हद तक खोए हुए समय की भरपाई की जा सके, जिसे उत्तरदाताओं द्वारा बहुत अंत में एक संक्षिप्त अवधि को छोड़कर अस्वीकार कर दिया गया था। दावेदारों को देय मुआवजे का निर्धारण करने में यह संक्षिप्त छूट बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी।

दावा संख्या **2-निष्क्रिय मशीनरी और उपकरणों के लिए क्षतिपूर्ति:Rs.84,59,615.00**

यह दावा इस अनुबंध के निष्पादन में तैनात मशीनरी और उपकरणों के लिए है, लेकिन विस्तारित अनुबंध अवधि के कारण, समय के बड़े हिस्से के लिए निष्क्रिय होना पड़ा। मैंने स्थल का निरीक्षण किया है। मेरा मानना है कि दावे में सार है। सभी पहलुओं पर उचित विचार करने के बाद, मैं 24 महीने की अवधि के लिए प्रति माह Rs.50,000.00 की राशि प्रदान करता हूँ जो Rs.12,00,000.00 पर आती है।

दावा संख्या **3-सामग्री और श्रम की बढ़ती लागत के कारण हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति:Rs.26,89,638.00**

भले ही सामग्री और श्रम की लागत में वृद्धि एक सामान्य विशेषता है जब इस तरह के इंजीनियरिंग अनुबंधों में अनुचित देरी हो जाती है, क्योंकि अनुबंध के अनुसार वृद्धि की अनुमति नहीं है, इसलिए दावा पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है।

दावा संख्या **4-अतिरिक्त कार्य करने के लिए क्षतिपूर्ति:Rs.19,00,225.00**

दावे में निम्नलिखित 4 मद शामिल हैं:

((i))	खुदाई की गई मिट्टी का परिवहन	Rs.12,05,000.00
((ख))	विलंबित अवधि के दौरान किए गए पेयजल शुल्क	5,62 रुपये, 570.00
(iii)	सामग्री के लिए स्थानांतरण शुल्क	रु. 1,01,405.00
((iv))	फ़िल्टर मीडिया के लिए स्थानांतरण शुल्क	Rs.31,250.00

उपरोक्त कार्य मुख्य अनुबंध के संबंध में किए गए हैं, लेकिन मालिक-उत्तरदाताओं द्वारा कुछ चूक और कमीशन के कारण अतिरिक्त वस्तुओं के रूप में निर्धारित किए गए हैं। दावेदारों ने अपने दावे के समर्थन में वाउचर और दस्तावेज जबरन पेश किए हैं। मैं प्रस्तुत किए गए सभी विवरणों से संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए, उपरोक्त दावे के खिलाफ, मुझे इस हद तक सम्मानित किया गया है कि मैं दस्तावेजों से संतुष्ट हूँ, जैसा कि नीचे दिया गया है:

वस्तु संख्या I	अन्य ठेकेदारों द्वारा कार्य स्थल पर फेंकी गई खुदाई की गई मिट्टी के परिवहन के लिए, अनुबंध देने से पहले
----------------	---

	लेकिन अनुबंध जमा करने के बाद 1,20 रुपये, 000.00।
वस्तु No.II	शून्य राशि
मद सं। III	Rs.50,000.00 वाहन के लिए साइट तक पहुंच की अनुपलब्धता के कारण सामग्री को मैनुअल रूप से स्थानांतरित करने की दिशा में।
वस्तु No.IV	Rs.25,000.00 फ़िल्टर मीडिया को जगह की कमी के लिए कई बार स्थानांतरित करने के शुल्क के लिए।

कुल दावा राशि प्रदान की गई: 1, 95 रुपये, 000.00 बनाम Rs.19,00,225.00

दावा संख्या **5**-मरम्मत और सुधार की लागत:मूल्यांकन की जाने वाली राशि। इस पर कोई पुरस्कार नहीं है क्योंकि यह परियोजना कार्य फिर से शुरू होने पर भविष्य की कार्रवाई को संदर्भित करता है।

दिलचस्प:दावेदार दिए गए सभी दावों पर प्रति वर्ष **18** प्रतिशत ब्याज के भी हकदार हैं, जो उस तारीख से प्रभावी है जिस दिन प्रत्यर्थियों को मध्यस्थता खंड का आह्वान करने वाला नोटिस दिया गया था (जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ) भुगतान की तारीख तक।

बैंक गारंटी:दावेदारों ने प्रदर्शन बैंक गारंटी राशि में **50** प्रतिशत की कमी के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लगभग **80** प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, और **449**

BATLIBOI पर्यावरण इंजीनियर लिमिटेड बनाम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड. [संजीव खन्ना, जे.] **450**

((एस. आई. सी.) में हुई भारी देरी को देखते हुए राशि में **50** प्रतिशत की कमी की जाएगी।"

6. आई. डी. **1** दिनांकित पुरस्कार में एच. पी. सी. एल. के प्रतिदावे को खारिज कर दिया गया है। **57.40** लाख, इस आधार पर कि देरी एच. पी. सी. एल. की चूक और कमीशन के कारण हुई थी। एच. पी. सी. एल. द्वारा मुआवजे/पुनर्वास लागत के लिए किए गए दावे। आई. डी. **1** लाख, आई. डी. **2** लाख के शेष कार्य की लागत और **9** लाख रुपये की पानी निकालने की लागत को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि वे भविष्य के कार्यों से संबंधित हैं और इसलिए, विचाराधीन मध्यस्थता के दायरे में नहीं आएंगे।

7. हमने बी. ई. ई. एल. के दावा संख्या **1,2** और **4** को अनुमति देते हुए, विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिए गए पूरे निर्णय और तर्क को जानबूझकर उद्धृत किया है। पुरस्कार में सबसे पहला गंभीर और स्पष्ट तथ्य यह है कि एच. पी. सी. एल. (जिसे पुरस्कार के उद्धृत हिस्से में मालिक और प्रतिवादी के रूप में संदर्भित किया गया है) **18** महीने की निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना को पूरा करने के रास्ते में आने वाली विभिन्न बाधाओं और बाधाओं को दूर करने में उचित और समय पर कार्रवाई नहीं करने से हुई अत्यधिक देरी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। यह निर्णय, हमारी राय में, तथ्यों और तर्कों के विश्लेषण और परीक्षण से रहित है। प्रासंगिक और भौतिक तथ्य और पक्षों के संबंधित रुख न तो समझने योग्य हैं और न ही उनका मूल्यांकन किया जा सकता है और निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई कारण नहीं दिया गया है। बिना किसी चर्चा और कारणों के कोई निष्कर्ष गैर-अनुपालन है और ए

एंड सी अधिनियम 5 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अधिदेश का उल्लंघन करता है, एक पहलू जिसकी हम बाद में जांच करेंगे। 8. दूसरी पेटेंट टुटि गणना और अधिभार के नुकसान के लिए अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत और लाभ/लाभप्रदता के नुकसान के लिए अन्य 10 प्रतिशत के पुरस्कार से संबंधित है। दोनों राशियों की मात्रा Rs.78,68,833/- प्रत्येक पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार, एच. पी. सी. एल. द्वारा बी. ई. ई. एल. को देय रु. <आई. डी. 1,666/- प्रदान किए गए हैं और रखे गए हैं। यह निर्णय उस विधि और तरीके के बारे में पूरी तरह से मौन होने के कारण है जिसमें मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने आदेशों की गणना की है। इसलिए, यह हमें और दलों को आश्चर्य करने के लिए छोड़ देता है

5 धारा 31-माध्यस्थम् अधिनिर्णय का प्रपत्र और विषय-वस्तु-(3) माध्यस्थम् अधिनिर्णय उन कारणों को बताएगा जिन पर यह आधारित है, जब तक कि -

(क) पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि कोई कारण नहीं दिया जाना चाहिए, या

(ख) पुरस्कार धारा 30 के तहत सहमत शर्तों पर एक मध्यस्थ पुरस्कार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

राशि प्रदान करने और गणना करने के लिए आधार। हम गणना के गुणों पर टिप्पणी या जांच नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी भी औचित्य और कारण का पूर्ण अभाव है जो दावा करने और दी गई राशि की मात्रा निर्धारित करने की अनुमति देता है। हम बाद में उक्त गणना के समर्थन में बी. ई. ई. एल. द्वारा प्रस्तुत चार्ट की जांच करेंगे, हालांकि इस स्तर पर हम निर्णय में स्पष्ट विरोधाभास को उजागर करना चाहेंगे, जो उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को बरकरार रखने का तीसरा आधार है।

9. हम ऊपर उद्धृत पुरस्कार के पहले पैराग्राफ का उल्लेख करते हुए, 'दावा संख्या 1-अधिभार और लाभ के नुकसान के लिए मुआवजा और लाभप्रदता' शीर्षक के तहत, तीसरे आधार की पुष्टि शुरू करते हैं। बी. ई. ई. एल. ने 27.08.1997 पर 48 महीने की देरी पर अधिभार और लाभ/लाभप्रदता के कारण नुकसान के लिए दावा संख्या 1 आधारित किया था। बी. ई. ई. एल. ने गणना के लिए अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत पर अधिभार के लिए और अन्य 10 प्रतिशत पर लाभ/लाभप्रदता के लिए विचार किया था। 3,38,38,460/-, "उनके द्वारा पहले से प्राप्त भुगतानों से समान प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए"। दावा संख्या 1 से संबंधित निर्णय के बाद के भाग में, विद्वान मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया है कि अनुबंध की कुल अवधि 49 महीने थी। मूल अनुबंध अवधि 18 महीने की थी, विस्तारित अवधि 31 महीने की थी। हालांकि, बी. ई. ई. एल. ने दावे के बयान में स्वीकार किया था कि उसने अनुमानों में अतिरिक्त खर्च के लिए 22 महीने का प्रावधान किया था। इसके अलावा, विद्वान मध्यस्थ ने आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त 3 महीने की अनुमति दी है, और अप्रत्याशित देरी के लिए, जैसे हड़ताल, लाल चेतावनी, और बल आकस्मिक घटनाओं के रूप में। दूसरे शब्दों में, विद्वान मध्यस्थ ने चूक के उद्देश्य से, 18 महीने की अवधि, यानी मूल अनुबंध अवधि, बी. ई. ई. एल. द्वारा प्रदान किए गए 4 महीने और आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रिया और आकस्मिक घटनाओं के कारण अन्य 3 महीने को बाहर कर दिया था। इस प्रकार, वह पूर्वनिर्धारित अवधि जिसके लिए बी. ई. ई. एल. अधिभार और लाभ/लाभप्रदता के नुकसान के लिए नुकसान/मुआवजे का दावा करने का हकदार है, 24 महीने है।

10. बी. ई. ई. एल. ने, जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस स्थिति को स्वीकार किया है कि ओवरहेड्स और प्रोफिट्स/प्रोफिटेबिलिटी के प्रति नुकसान को प्रतिशत सूत्र, कार्य के निष्पादन के साथ भिन्न रूप को लागू करके प्राप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार, हमारी राय में, अधिभार और लाभ/लाभप्रदता के प्रति नुकसान की गणना गैर-निष्पादित कार्य के लिए देय भुगतान पर की जानी चाहिए, और निष्पादित कार्य के लिए प्राप्त/प्राप्य भुगतान को बाहर रखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बी. ई. ई. एल. द्वारा निष्पादित कार्य के मूल्य के आधार पर, आनुपातिक 451

BATLIBOI पर्यावरण इंजीनियर लिमिटेड बनाम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड. [संजीव खन्ना, जे.] 452

नुकसान/मुआवजे की गणना करने के लिए राशि को अधिभार पर खर्च के प्रतिशत के रूप में और लाभ/लाभ योग्यता के नुकसान के लिए नुकसान के रूप में कम किया जाना चाहिए। अधिभार पर खर्च और लाभ की हानि के लिए नुकसान आनुपातिक हैं, और किए गए और भुगतान किए गए/देय कार्य के लिए देय नहीं हैं। कार्य के निष्पादन पर भुगतान में देरी की भरपाई अलग से की जानी

चाहिए। 11. यह एक स्वीकृत पद है और पुरस्कार में विशिष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि अनुबंध का कुल मूल्य रु। 5,74,35,213.00p। पुरस्कार के पहले के एक पैराग्राफ में, जिसे पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है, विद्वान मध्यस्थ ने आर. ए. बिल संख्या 4 दिनांक 31.08.1993 का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार बी. ई. ई. एल. ने रु. 1,21,95,859.68p का काम पूरा कर लिया था। यह भी एक स्वीकृत और स्वीकृत स्थिति है कि आर. ए. बिल संख्या 37 के अनुसार, जिस तारीख को काम बंद हुआ था, उस तारीख तक काम का मूल्य रु। 2,92,07,619.13p को निष्पादित किया गया था। दूसरे शब्दों में, बी. ई. ई. एल. ने रुपये का भुगतान किया था और प्राप्त किया था। 2,92,07,619.13-एच. पी. सी. एल. से समय-समय पर, 01.09.1993 और 30.03.1996 अवधि के बीच। अस्सी प्रतिशत काम पूरा हो चुका था। बी. ई. ई. एल. को आर. ए. संख्या 37 तक चालू खाते के बिलों के संदर्भ में कुल रु. 4,14,03,478.81p का भुगतान प्राप्त हुआ है। शेष कार्य रु। 1,14,87,042.00p। रुपये का बीस प्रतिशत. 1,14,03,478.81 Rs. 22,97,408.40p है। इसके अलावा, बी. ई. ई. एल. रुपये 2,92,07,619.13 के काम के निष्पादन में देरी के लिए मुआवजे का हकदार है-भुगतान किए जाने की तारीख तक, हालांकि, पुरस्कार रुपये के भुगतान का निर्देश देता है। 16.05.1997 से प्रभावी रूप से दिए गए सभी दावों पर प्रति वर्ष 18 प्रतिशत ब्याज।

12. यह पुरस्कार बिना किसी चर्चा, स्पष्टीकरण और कारण के प्रदर्शन बैंक गारंटी राशि को 50 प्रतिशत तक कम कर देता है।

13. पुरस्कार में की गई गणना और मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए सिद्धांत या विधि को सही ठहराने के लिए, बी. ई. ई. एल. ने हडसन के सूत्र का उल्लेख किया है और मैकडर्मोट में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है।

इंटरनेशनल इंक. वी.बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड और अन्य। 6, और एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण 7, ए. टी. बृज पॉल सिंह और अन्य बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसले के अलावा।

गुजरात 8, और उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णय।

6 (2006) 11 एस. सी. सी. 181 (संक्षेप में, मैकडर्मोट इंटरनेशनल इंक.)। 7 (2015) 3 एस. सी. सी. 49 (संक्षेप में, एसोसिएट बिल्डर्स)।

8 (1984) 4 एससीसी 59.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

14. मैकडर्मोट इंटरनेशनल इंक. में इस न्यायालय ने पैराग्राफ 102 से 107 में नुकसान की गणना के विभिन्न तरीकों का उल्लेख किया है। विशेष रूप से, हडसन के सूत्र, एमडेन के सूत्र और आइकले के सूत्र का संदर्भ निम्नलिखित शब्दों में दिया गया है:

“ क्षति की गणना की विधि

102. [एड.: पैरा 102 को आधिकारिक शुद्धिपत्र सं. एफ. 3/Ed.B.J./52/2006 दिनांकित 31-7-2006]। हालांकि, नुकसान की गणना की विधि क्या होनी चाहिए, यह एक सवाल है जो अब विचार के लिए उत्पन्न होता है। इससे पहले कि हम इस संबंध में पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों का विज्ञापन करें, हम एम. एन. गंगप्पा बनाम आत्माकुर नागभूषणम सेट्टी एंड कंपनी में देख सकते हैं। [(1973) 3 एस. सी. सी. 406] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि क्षति की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली विधि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

102-ए. हजनि के आकलन में, अदालत को केवल सख्त कानूनी दायित्वों पर विचार करना चाहिए, न कि एक ठेकेदार की अपेक्षाओं पर, चाहे वह कितना भी उचित क्यों न हो, कि दूसरा कुछ ऐसा करेगा जिसे करने के लिए उसने कोई कानूनी दायित्व नहीं माना है। (कोलचेस्टर लिमिटेड के लावरैक बनाम वुड्स देखें) [(1967) 1 क्यू. बी. 278; (1966) 3 सभी ई. आर. 683; (1966) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 706 (सी. ए.)], ऑल ई. आर. पी. 690 जी.)

103. मध्यस्थ ने एमडेन फॉर्मूला का सहारा लेकर दावे की मात्रा निर्धारित की। विद्वान मध्यस्थ ने अन्य सूत्रों का भी उल्लेख किया, लेकिन, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, राय दी कि एमडेन सूत्र व्यापक रूप से स्वीकृत है।

104. यह विवाद में नहीं है कि एम. आई. आई. ने उक्त दावे को साबित करने के लिए श्री डी. जे. पार्सन से पूछताछ की थी। उक्त गवाह ने मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा प्रकाशित "चेंज ऑर्डर्स, ओवरटाइम, प्रोडक्टिविटी" नामक एक नियमावली में निर्धारित सूत्र के आधार पर बढ़े हुए अधिभार और लाभ के नुकसान की गणना की, जिसे आमतौर पर एमडेन सूत्र के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि बढ़े हुए अधिभार और लाभ के नुकसान की गणना के लिए निर्माण अनुबंधों में उक्त सूत्र को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है कि श्री डी. जे. पार्सन ने अमेरिकी डॉलर 1,109,500 पर अतिरिक्त परियोजना प्रबंधन लागत लाई थी। हम इस समय इस संबंध में लागू विभिन्न सूत्रों पर ध्यान दे सकते हैं।

453

BATLIBOI पर्यावरण इंजीनियर लिमिटेड बनाम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड. [संजीव खन्ना, जे.] 454 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

(क) हडसन सूत्र: हडसन के बिल्टिंग एंड इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में, हडसन फॉर्मूला को निम्नलिखित शब्दों में कहा गया है:

“अनुबंध प्रमुख कार्यालय सी. ई. ओवरहेड

× अनुबंध राशि

× देरी की अवधि "

और लाभ का प्रतिशत

अनुबंध की अवधि

हडसन फॉर्मूला में, मुख्य कार्यालय सीई ओवरहेड प्रतिशत अनुबंध से लिया जाता है। हालाँकि हडसन फॉर्मूला को कई मामलों में न्यायिक समर्थन प्राप्त हुआ है, लेकिन इसकी मुख्य रूप से आलोचना की गई है क्योंकि यह लागत की गणना के लिए अनुबंध से हेड ऑफिशियल ओवरहेड प्रतिशत को कारक के रूप में अपनाता है, और यह ठेकेदार की वास्तविक हेड ऑफिशियल लागत से बहुत कम या कोई संबंध नहीं रख सकता है।

(ख) एमडेन सूत्र: एमडेन के निर्माण अनुबंध और अभ्यास में, एमडेन सूत्र को निम्नलिखित शब्दों में कहा गया है:

“हेड ऑफिस सी. ई. ओवरहेड और प्रोफिट टी × अनुबंध राशि × देरी की अवधि "100

अनुबंध की अवधि

एमडेन फॉर्मूला का उपयोग करते हुए, मुख्य कार्यालय सी. ई. ओवरहेड प्रतिशत को कुल ओवरहेड लागत और ठेकेदार के संगठन के लाभ को कुल कारोबार से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। इस सूत्र में अनुबंध में निहित लोगों के बजाय ठेकेदार के वास्तविक प्रमुख कार्यालय सी. ई. ओवरहेड और लाभ प्रतिशत का उपयोग करने का लाभ है। इस सूत्र को व्यापक रूप से लागू किया गया है और इसे नॉरवेस्ट होल्स्ट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम नॉरवेस्ट होल्स्ट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड सहित कई मामलों में न्यायिक समर्थन प्राप्त हुआ है। कॉपाथोक सोसायटी लिमिटेड [17-2-1998, [1998] ईडब्ल्यूएचसी टेक्नोलॉजी 339 पर निर्णय लिया गया], बीचवुड डेवलपमेंट कं. (स्कॉटलैंड) लिमिटेड बनाम मिचेल [डिसाइडेड ऑन 21-2-2001, (2001) CILL 1727] और हार्वे शॉपी टीटर्स लिमिटेड बनाम आदि लिमिटेड. [6-3-2003, (2004) 2 पर निर्णय सभी ER 982: [2003] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 1757]।

(ग) आइकले सूत्र: आइश्ले फॉर्मूला अमेरिका में विकसित किया गया था और इसका नाम आर्म्ड सर्विसेज बोर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपीलर्स, आइश्ले कॉर्पोरेशन द्वारा सुने गए एक मामले से लिया गया था। इसे निम्नलिखित तरीके से लागू किया जाता है:

चरण 1.

अनुबंध बिलिंग

× टी ए एल ओ वी आर एच ई ए डी एफ ओ आर

= ओवरहेड आबंटन योग्य

अनुबंध की अवधि

अनुबंध के लिए

अनुबंध के लिए कुल बिलिंग

अवधि

चरण 2

आबंटित ओवरहेड

=

दैनिक अधिभार दर

अनुबंध के कुल दिन

चरण 3.

दैनिक अनुबंध

× दिनों की संख्या

= की राशि

ऊपर की दर

देरी

ऊपर से अवशोषित नहीं "

इस सूत्र का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अवसर के नुकसान को साबित करना संभव नहीं है और दावा वास्तविक लागत पर आधारित है। इस सूत्र से यह देखा जा सकता है कि अनुबंध अवधि के दौरान कुल शीर्ष कार्य का निर्धारण पहले परियोजना के लिए अनुबंध अवधि में किए गए कार्य के मूल्य की तुलना ठेकेदार द्वारा अनुबंध अवधि के लिए किए गए कार्य के मूल्य से करके किया जाता है। ठेकेदार के लिए हेड ऑफिस ओवरहेड्स का एक हिस्सा उसी अनुपात में आवंटित किया जाता है और विशेष अनुबंध के लिए एकमुश्त राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है। विशेष अनुबंध के लिए आवंटित हेड ऑफिस सी. ई. ओवरहेड की राशि को अनुबंध अवधि से विभाजित करके साप्ताहिक राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है। दावा की गई कुल राशि देने के लिए विलंब की अवधि को साप्ताहिक राशि से गुणा किया जाता है। आइकले फॉर्मूला को अमेरिका के फेडरल सर्किट कोर्ट द्वारा ओवरहेड खर्चों के लिए एक ठेकेदार को मुआवजा देने के लिए विशेष साधन के रूप में माना जाता है।

105. हमारे सामने कई अमेरिकी फैसलों का उल्लेख श्री दीपांकर गुप्ता ने उनके इस निवेदन की सहायता के लिए किया है कि एमडेन फॉर्मूला को तब से अमेरिकी अदालतों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है क्योंकि निकॉन इंक बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका [10-6-2003 (यू. एस. सी. ए. फेड सिर), 331 एफ. 3 डी 878 (फेड. सर। 2003)], ग्लैडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम बाल्टीमोर के महापौर और नगर परिषद [25-9-2002, 807 A. 2d 1141 (2002) पर निर्णय लिया गया: 147 मो. ऐप. 149] और चार्ल्स जी. विलियम कंस्ट्रक्शन इंक. बनाम सफेद [271 F 3d 1055 (फेड। सर। 2001)]।

106. हम इस मामले में गहराई से जाने का इरादा नहीं रखते हैं क्योंकि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि विभिन्न सूत्र **455** में लागू किए जा सकते हैं।

BATLIBOI पर्यावरण इंजीनियर लिमिटेड बनाम

परिस्थितियों और यह प्रश्न कि क्या नुकसान की गणना किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक या दूसरे सूत्र का सहारा लेकर की जानी चाहिए, मुख्य रूप से मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में आएगा।

107. यदि विद्वान मध्यस्थ, इसलिए, नुकसान की राशि का आकलन करने में एमडेन फॉर्मूला लागू करता है, तो उसे इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देने वाली त्रुटि करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।"

15. मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. धारा 55 9 और 73 10 को संदर्भित करता है

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 11, जो कार्यस्थल पर प्रदर्शन करने में विफलता के प्रभाव से संबंधित है।

9 धारा 55-अनुबंध के उस समय में, जिसमें अनुबंध आवश्यक है, प्रदर्शन करने में विफलता का प्रभाव-जब किसी अनुबंध का कोई पक्ष किसी निश्चित समय पर या उससे पहले या निर्दिष्ट समय पर या उससे पहले कुछ काम करने का वादा करता है, और निर्दिष्ट समय पर या उससे पहले ऐसा कोई काम करने में विफल रहता है, तो अनुबंध, या इसका इतना हिस्सा जो निष्पादित नहीं किया गया है, वादा करने वाले के विकल्प पर अमान्य हो जाता है, यदि पक्षों का इरादा था कि उस समय अनुबंध का सार होना चाहिए।

इस तरह की विफलता का प्रभाव तब होता है जब समय आवश्यक नहीं होता है।—यदि यह पक्षों का इरादा नहीं था कि समय अनुबंध का सार होना चाहिए, तो अनुबंध निर्दिष्ट समय पर या उससे पहले ऐसा करने में विफलता के कारण अमान्य नहीं हो जाता है; लेकिन वादा करने वाला इस तरह की विफलता से हुए किसी भी नुकसान के लिए वादा करने वाले से मुआवजे का हकदार है।

सहमति के अलावा अन्य समय पर प्रदर्शन की स्वीकृति का प्रभाव।—यदि वचनदाता द्वारा सहमत समय पर अपने वादे को पूरा करने में विफलता के कारण रद्द होने योग्य अनुबंध की स्थिति में, वचनदाता सहमत समय के अलावा किसी भी समय ऐसे वादे के निष्पादन को स्वीकार करता है, तो वचनदाता सहमत समय पर वादे के गैर-निष्पादन के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता है, जब तक कि, ऐसी स्वीकृति के समय, वह वचनदाता को ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना नहीं देता है।

10 धारा 73-अनुबंध के उल्लंघन के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति।- जब कोई अनुबंध तोड़ा जाता है, तो जो पक्ष इस तरह के उल्लंघन के लिए पर्याप्त होता है, वह उस पक्ष से, जिसने अनुबंध तोड़ा है, किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होता है, जो स्वाभाविक रूप से इस तरह के उल्लंघन से चीजों के सामान्य क्रम में उत्पन्न हुआ था, या जिसे पक्षकारों को पता था कि जब उन्होंने अनुबंध किया था, तो इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने की संभावना थी। इस तरह का मुआवजा उल्लंघन के कारण हुए किसी भी दूरस्थ और अप्रत्यक्ष नुकसान या क्षति के लिए नहीं दिया जाना है।

अनुबंध द्वारा बनाए गए दायित्वों के समान दायित्वों का निर्वहन करने में विफलता के लिए क्षतिपूर्ति।जब अनुबंध द्वारा बनाए गए दायित्वों से मिलता-जुलता कोई दायित्व वहन किया गया है और उसे निर्वहन नहीं किया गया है, तो इसे निर्वहन करने में विफलता से घायल कोई भी व्यक्ति चूक में पक्ष से समान मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है, जैसे कि ऐसे व्यक्ति ने इसे निर्वहन करने का अनुबंध किया था और अपने अनुबंध को तोड़ा था।

व्याख्या-अनुबंध के उल्लंघन से होने वाले नुकसान या क्षति का अनुमान लगाने में, अनुबंध के गैर-प्रदर्शन के कारण होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए मौजूद साधनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

11 संक्षेप में, अनुबंध अधिनियम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

अनुबंधों में जहां समय महत्वपूर्ण है, और अनुबंध के उल्लंघन के कारण होने वाले नुकसान की गणना, क्रमशः, और यह बताती है कि ये धाराएं न तो मोड निर्धारित करती हैं और न ही मुआवजे के लिए नुकसान की गणना कैसे और किस तरीके से की जानी है।

चूँकि गणना परिचर तथ्यों और परिस्थितियों और नुकसान की गणना करने के तरीकों पर निर्भर करती है, इसलिए इसकी मात्रा कैसे निर्धारित की जानी चाहिए, यह एक ऐसा मामला है जो मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र और निर्णय के भीतर आता है।

16. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक ठोस कानूनी और सही प्रस्ताव है। हालांकि, नुकसान की गणना सनकी और बेतुकी नहीं होनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप एक पक्ष के लिए दूसरे की कीमत पर अप्रत्याशित नुकसान और इनाम होना चाहिए। नुकसान की गणना कपटपूर्ण नहीं होनी चाहिए। नुकसान को हुए नुकसान के अनुरूप होना चाहिए। नियोक्ता के कारण काम में देरी के कारण होने वाले नुकसान के दावे में, ठेकेदार अनुबंध के उल्लंघन से हुए नुकसान का हकदार है और जहां तक पैसा क्षतिपूर्ति कर सकता है। पक्ष को उसी स्थिति में रखा जाना चाहिए, नुकसान के साथ, जैसे कि अनुबंध किया गया था। सिद्धांत यह है कि जिस पक्ष ने चोट पहुँचाई है, उसे दी गई राशि उतनी ही होनी चाहिए जितनी उसने अर्जित या अर्जित की होगी, यदि उसने वह गलती नहीं की थी जिसके लिए उसे मुआवजा दिया जा रहा है। 12

17. हम बाद में हडसन के सूत्र को कैटेचाइज करेंगे, इस स्तर पर यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि विद्वान मध्यस्थ किसी भी सूत्र या विधि का निर्दिष्ट रूप से उल्लेख नहीं करता है, और अधिभार और प्रोफिट्स/प्रोफिटेबिलिटी के कारण नुकसान के शीर्ष के तहत नुकसान की गणना करने का अधिकार देता है। जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, यह पुरस्कार अनुबंध अधिनियम की धारा 55 और 73 का उल्लेख करता है।

18. पुरस्कार और विषय-वस्तु की जांच करने के बाद, हम अब बी. ई. ई. एल. द्वारा अतिरिक्त या नई सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत किए गए चार्ट का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि यह मध्यस्थता कार्यवाही में किए गए दावों के बयान के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें अदालत के लाभ के लिए "स्पष्टीकरण" शीर्षक वाला कॉलम जोड़ा गया है। चार्ट इस प्रकार है:

12 देखें-रॉबिन्सन बनाम हरमन (1848) 1 पूर्व 850 855 पर और लिविंगस्टोन बनाम रॉयाडर्स कोल कंपनी (1879-80) L. R. 5880 मामले 25 457

BATLIBOI पर्यावरण इंजीनियर लिमिटेड बनाम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. [संजीव खन्ना, जे.] 458 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

श्री. नहीं।	विशिष्टताएँ	राशि (रु.)	स्पष्टीकरण
1	अनुबंध राशि		5,74,35,213.00 कुल अनुबंध मूल्य
2	उपरोक्त राशि में अधिभार (10 प्रतिशत) और लाभ (10 प्रतिशत) शामिल हैं।		1,14,87,042.00 20% रुपये का 5,74,35,213.00 (1) अर्थात् अनुबंध मूल्य
3	कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा	22 महीनों	हालाँकि याचिकाकर्ता ने अनुमान लगाया कि साइट को 22 महीने यानी अनुबंध अवधि से अधिक 4 महीने के लिए बनाए रखना

			होगा।
4	खर्च और लाभ प्रति माह [(2) (3) से विभाजित]	5,22,138.27 प्रति माह	कुल ओवर हेड्स और प्रोफिट्स को काम के महीनों से विभाजित करके (22 महीने)
5	आर. ए. बिल संख्या 4 दिनांक 31.08.1993 तक किए गए कार्य का मूल्य		1,21,95,859.68 अनुबंध अवधि 22 फरवरी 1992 से 31.08.1993 यानी 18 महीने तक थी।
6	31.08.1993 तक प्राप्त प्रो-रेटा ओवरहेड्स और लाभ	24,39,171.00	20% (5) से। चूंकि याचिकाकर्ता को (5) पर बिल का भुगतान प्राप्त हुआ है, इसलिए (5) पर बिल द्वारा कवर किए गए काम के लिए अधिभार और लाभ मध्यस्थ द्वारा (7) में काट लिए गए हैं।
7	कुल नुकसान 01.09.1993 [(2)-(6)] पर निर्भर करता है	90,47,871.00	उपरोक्त के अनुसार, 22 महीने के काम के लिए, याचिकाकर्ता को रु। 1,14,87,042.00-(2) अधिभार और लाभ की ओर। हालाँकि, इसमें से याचिकाकर्ता को रु। 24,39,171.00-(6), वही काट लिया गया है।

श्री. नहीं।	विशिष्टताएँ	राशि (रु.)	स्पष्टीकरण
			Rs.90,47,871.00-अनुबंध अवधि के लिए अधिभार

			और लाभ के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्य बकाया है।
8	महीनों में देरी	24 महीनों	खर्च किया गया कुल समय 49 महीने (एसएलपी का Pg.56) (22 फरवरी 1992 से 31 मार्च 1996) था। इसमें से, चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा काम के लिए 22 महीनों पर विचार किया गया था, इसलिए मध्यस्थ द्वारा 49 महीनों से कटौती की गई थी। (एसएलपी का Pg.56)। मध्यस्थ द्वारा फोर्स मैजेयर के कारण 3 महीने की और अवधि काट ली गई है। इस प्रकार $49 - 22 - 3 = 24$ मो. एन. टी. एच. एस. ई. एक्स. टी. आर. ए. डब्ल्यू. ओ. आर. के। (एसएलपी का Pg.56)।
9	अतिरिक्त अवधि के दौरान अपेक्षित अधिभार और लाभ [(8) * (4)]		1,25,31, 318.48 यह खर्च किए गए अतिरिक्त समय यानी 24 महीने के लिए राशि है। 244 महीनों को प्रति माह ओवरहेड और लाभ से गुणा किया जाता है। $24 * \text{रु. } 5,22,138.27 = \text{रु. } 1,25,31,318.48$

श्री. नहीं।	विशिष्टताएँ	राशि (रु.)	स्पष्टीकरण
10	विस्तारित अवधि के दौरान निष्पादित कार्य का मूल्य 30.03.1996 (आर. ए. बिल No.37) तक		2,92,07, 619.13 यह राशि विस्तारित अवधि अर्थात् अगस्त 1993 से मार्च 1996 के दौरान किए गए कार्य के लिए प्राप्त राशि है।
11	विस्तारित अवधि के दौरान प्रो-राटा ओवरहेड्स और प्रोफिट्स प्राप्त हुए।	58,41, 523.80	यह 2,92,07,619.13 (10) का 20 प्रतिशत है। चूंकि याचिकाकर्ता को (10) पर बिल का भुगतान प्राप्त हुआ है, इसलिए (10) पर बिल द्वारा कवर किए गए काम के लिए ओवरहेड्स और प्रोफिट को मध्यस्थ द्वारा (11) में काट लिया गया है।
12	कुल नुकसान 27.08.1997 [(9)-(11)] तक हुआ।	66,89, 791.68	यह 24 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए ओवरहेड और लाभ का नुकसान है। जैसा कि (9) में कहा गया है, इसके एफ या 24 महीने के अतिरिक्त समय का ओवरहेड्स और पी. आर. रु. 1,25,31,318.48 था। चूंकि, याचिकाकर्ता को Rs.58,41,523.80 (11) की राशि प्राप्त हुई है, इसलिए मध्यस्थ द्वारा इसकी

			कटौती की गई है।
13	27.08.1997 [(7)-(12)] तक इस गणना पर अधिभार और लाभ पर कुल नुकसान		1,57,37, 665.68 यह राशि अनुबंध अवधि के दौरान देय ओवरहेड और लाभों के साथ- साथ 24 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए ओवरहेड और लाभों का योग है। मध्यस्थ द्वारा पुरस्कृत (एसएलपी का Pg.56)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

19. चार्ट में दिए गए चार्ट और स्पष्टीकरण, हम मानते हैं, गणना और नुकसान के पुरस्कार को किसी भी तरह से उचित ठहराने के लिए पीछे की ओर काम करने के लिए एक विचार और व्यर्थ तथ्य हैं। ये व्याख्याएँ निम्नलिखित कारणों से अतार्किक और तर्कहीन प्रतीत होती हैं:

(i) S.No.7 बी. ई. ई. एल. द्वारा कुल नुकसान की गणना Rs.90,47,871/- के रूप में करता है, जो कि 18 महीने की अवधि के लिए है। गणना अनदेखा करती है और दावा विवरण में बी. ई. ई. एल. द्वारा उल्लिखित 4 महीने की अवधि को नहीं जोड़ती है। इसके अलावा, मध्यस्थ ने आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रिया और आकस्मिक घटनाओं के लिए 3 महीने की एक और अवधि जोड़ी थी। इस प्रकार, S.No.7 में संदर्भित तिथि 01.09.1993 गलत है और पुरस्कार में की गई गणना का आधार नहीं है। S.No.7 सात महीने की अवधि को ध्यान में रखने में विफल रहता है, जिसे पुरस्कार के अनुसार जोड़ा जाना है।

(ii) Rs.90,47,871/- का शुल्क कार्य के अभाव में और वास्तव में 01.09.1993 के बाद भुगतान के लिए प्रासंगिक होता। हालांकि, यह एक स्वीकृत और स्वीकृत स्थिति है कि काम के आनुपातिक मूल्य के पूरा होने पर 2,92,07,619.13p का भुगतान 01.09.1993 से 30.03.1996 के बीच अलग-अलग तिथियों पर किया गया था। प्रोफिट्स/प्रोफिटेबिलिटी और ओवरहेड्स के नुकसान के कारण दावा, जैसा कि ऊपर समझाया गया है और कई निर्णयों और ग्रंथों के संदर्भ में बाद में भी स्पष्ट किया गया है, भुगतान योग्य है यदि और जब सहमत या संविदात्मक अवधि के बाद काम पूरा करने में देरी के कारण ऑफ-साइट और ऑन-साइट ओवरहेड्स की लागत में वृद्धि होती है जो नियोक्ता के कारण होती है। 13 इसके अलावा, लाभ अर्जित करने की क्षमता के कारण होने वाले नुकसान का भुगतान तब किया जाता है जब ठेकेदार की लाभ अर्जित करने की क्षमता को संबंधित अनुबंध में लंबे समय तक बनाए रखने के कारण प्रभावित किया जाता है।

13 इस मामले में, जैसा कि देखा गया है, अनुबंध लागत में वृद्धि/वृद्धि आदि के कारण होने वाले नुकसान के मुआवजे के दावे पर रोक लगाता है। हम इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। ऐसे खंडों की व्याख्या और वैधता इस अपील का विषय नहीं है। जब ऐसे खंड, जो स्पष्ट रूप से एकतरफा होते हैं और प्रतिरक्षा का उल्लंघन करते हैं, न्यायिक जांच के अधीन होते हैं, तो अदालतें/न्यायाधिकरण हमेशा न्यायपूर्ण और निष्पक्ष राहत देने के लिए प्रतिबंधात्मक तरीके से खंडों की व्याख्या करते हैं। अदालतों को हस्तक्षेप करने में देरी करनी चाहिए, जब तक कि पुरस्कार ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 में निर्धारित मापदंडों के दायरे में नहीं आता है।

461

BATLIBOI पर्यावरण इंजीनियर लिमिटेड बनाम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. [संजीव खन्ना, जे.] 462

अर्जित मौद्रिक लाभ में वृद्धि और लाभ अर्जित करने के लिए कहीं और जाने के लिए स्वतंत्र होने के बिना जो वह अन्यथा करने में सक्षम हो सकता है।बी. ई. ई. एल. के मामले में ऐसा नहीं है कि वे काम के निष्पादन में देरी के कारण लागत बढ़ाने या बढ़ाने के हकदार हैं।उल्लेखनीय है कि सामग्री और श्रम की लागत में वृद्धि के कारण हुए नुकसान के मुआवजे के लिए दावा संख्या 3 को विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है, क्योंकि कीमतों/लागतों में वृद्धि अनुबंध की शर्तों द्वारा बाधित है।

(iii) इसलिए, Rs.90,47,871/- के S.No.7 के तहत नुकसान की गणना अस्थिर है और इसे किसी भी गणना और अनुबंध अधिनियम के संदर्भ में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

(iv) चार्ट के अनुसार, Rs.90,47,871/- के अलावा, मध्यस्थ ने S.No.12 पर, Rs.66,89,794.68p की एक और राशि प्रदान की है।24 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए अधिभार और लाभ के नुकसान के कारण, यानी 27.08.1997 तक।S.No.12 के अनुसार वित्तीय उपाय विस्तारित अवधि के दौरान प्रो रेटा ओवरहेड्स और प्रोफिट्स को कम करने के बाद किया जाता है जैसा कि S.No.9 में उल्लेख किया गया है।गणना तर्क को झुठलाती है और इसकी अवहेलना करती है।यह स्पष्ट रूप से मुआवजे और नुकसान के लिए दोगुना भुगतान के बराबर है, क्योंकि यह ध्यान देने में विफल रहता है कि रुपये की S.No.7 में उल्लिखित राशि। 90,47,871-ओवरहेड्स और प्रोफिट्स/प्रोफिटेबिलिटी के लिए मुआवजे के कारण है।इसलिए, अधूरे कार्य के मूल्य का 20 प्रतिशत पहले ही गणना में शामिल किया जा चुका था और S.No.7 के तहत प्रदान किया गया था।तारीख 27.08.1997 सबसे अच्छा है, बी. ई. ई. एल. की एक धारणा है और पुरस्कार से कहीं भी उल्लेख या समझने योग्य नहीं है।

20. हमने आंशिक रोकथाम के मामले में मुआवजे/नुकसान के दावे की गणना के लिए लागू सिद्धांत का संक्षेप में उल्लेख किया है, यानी, जहां नियोक्ता द्वारा उल्लंघन मौलिक नहीं है और बिल्डर/ठेकेदार को काम बंद करने का अधिकार नहीं देता है, या मौलिक होने के नाते, बिल्डर/ठेकेदार द्वारा अस्वीकृति के रूप में नहीं माना जाता है।ऐसे मामलों में मुआवजे/नुकसान का माप कम लाभप्रदता या किए गए काम के अतिरिक्त खर्च से उत्पन्न लाभ का नुकसान है।14 एक दिए गए मामले में, जहां द्वारा एक मौलिक उल्लंघन है

14 हडसन के भवन अनुबंध (10 वीं संस्करण) पृष्ठ 450 देखें,596.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

नियोक्ता, हालांकि, बिल्डर/ठेकेदार तुरंत अनुबंध को अस्वीकृत मानने का विकल्प नहीं चुनता है, फिर भी वह अपूर्ण काम पर लाभ के नुकसान के लिए दावा करने का हकदार हो सकता है।ऑफ साइट खर्च या ओवरहेड्स सभी प्रशासनिक या कार्यकारी लागतें हैं जो प्रबंधन पर्यवेक्षण या पूंजी परिव्यय के लिए आकस्मिक हैं जो संचालन शुल्क से अलग हैं।इन शुल्कों को काम या नौकरी की एक धारा के लिए उचित रूप से नहीं लिया जा सकता है, और इसके बजाय वितरित किया जा सकता है क्योंकि वे सामान्य व्यवसाय या ठेकेदार/बिल्डर के काम से संबंधित हैं जो किए जा रहे हैं या किए जाने वाले हैं, क्योंकि ओवरहेड्स पूरी तरह से बिल्डर/ठेकेदार के व्यवसाय से संबंधित हैं।21. ओवरहेड्स और प्रोफिट्स के नुकसान का पता लगाने के लिए हडसन, एमडेन या आइकले जैसे सूत्रों का उपयोग न्यायिक रूप से किया गया है।

पीक कंस्ट्रक्शन (लिवरपूल) लिमिटेड बनाम मैककिनी फाउंडेशन लिमिटेड 15, व्हिटल बिल्डर्स बनाम चेस्टरले-स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 16, और जे. एफ. फिनेगन लिमिटेड बनाम शेफी एल्ड सिटी काउंसिल 17 के अंग्रेजी मामलों में अनुमोदित

एलिस-डॉन बनाम टोरंटो के पार्किंग प्राधिकरण का कनाडाई मामला 18.ये तीन सूत्र सैद्धांतिक गणितीय समीकरणों से संबंधित हैं, लेकिन ये तथ्यात्मक मान्यताओं पर आधारित हैं, और इसलिए ये तीन अलग-अलग और असंबंधित मुआवजे/नुकसान का उत्पादन कर सकते हैं।इसलिए, किसी विशेष समीकरण या विधि को लागू करते समय, धारणाओं की जांच की जानी चाहिए, और तथ्यों और परिस्थितियों में धारणाओं की संतुष्टि का पता लगाया जाना चाहिए।

22. हडसन ने अपनी पुस्तक 'बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द कम्प्यूटेशन ऑफ डैमेज' के 10 वें संस्करण में जो सूत्र सुझाया है, वह अनुबंध मूल्य के अनुपात के रूप में प्रमुख आधिकारिक सीई और प्रोफिट प्रतिशत लेता है।सूत्र में यह माना गया है कि बिल्डर/ठेकेदार द्वारा तय किया गया लाभ वास्तव में उसके द्वारा कहीं और अर्जित करने में सक्षम है यदि बिल्डर/ठेकेदार उचित समय पर अनुबंध छोड़ने के लिए स्वतंत्र था।यह सूत्र तीन मान्यताओं पर आधारित है।पहला, कि ठेकेदार मूल्य निर्धारण करते समय लागत को आदतन या अन्यथा कम नहीं आंक रहा है; दूसरा, उस समय लाभ तत्व यथार्थवादी था;

और अंत में, बाजार की स्थितियों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी और अनुबंध अवधि के अंत में उसे उसी सामान्य स्तर की लाभप्रदता का काम उपलब्ध होगा। इनसे होती है संतुष्टि

15 (1970) 1 बीएलआर 114। 16 (1987) 40 बीएलआर 82। 17 (1988) 43 बीएलआर 124। 18 (1978) 28 बीएलआर 98।

463

BATLIBOI पर्यावरण इंजीनियर लिमिटेड बनाम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड. [संजीव खन्ना, जे.] 464 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

जब हम नुकसान की गणना के लिए हडसन के सूत्र को लागू करते हैं तो धारणाओं का पता लगाया जाना चाहिए। दावेदार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सामग्री प्रस्तुत की जानी चाहिए कि हडसन के सूत्र को लागू करने के लिए धारणाएं पूरी होती हैं।

23. आम तौर पर, जब किसी अनुबंध को पूरा करने में देरी होती है और ठेकेदार का दावा है कि नौकरी से उसकी आय में कमी और इसलिए उसके/उसके व्यवसाय के कारोबार से उत्पन्न नुकसान, और कार्यबल खर्चों के रूप में ओवरहेड्स के लिए भी जो अन्य अनुबंधों में लगाए जा सकते थे, मध्यस्थ या अदालत के समक्ष किसी भी अनुनय को सहन करने के दावे, बिल्डर/ठेकेदार को यह साबित करना होता है कि अन्य काम उपलब्ध था जो वह देरी के लिए नहीं था, तो निविदा के लिए निमंत्रण प्रस्तुत करके जो अन्य काम करने की अपर्याप्त क्षमता के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। कारोबार में गिरावट को प्रदर्शित करने और यह स्थापित करने के लिए कि यह परिणाम बाहरी कारणों के बजाय विशेष देरी से है, इसे लेखा पुस्तकों से भी साबित किया जा सकता है। यदि देरी के परिणामस्वरूप कारोबार का नुकसान स्थापित नहीं होता है, तो यह केवल धन की प्राप्ति में देरी है, और इस तरह, बिल्डर/ठेकेदार केवल नियोजित पूंजी पर ब्याज का हकदार है, न कि लाभ का, जिसका भुगतान किया जाना चाहिए। संपत्ति और संपत्ति के मामले में उच्च न्यायालय का न्यायपीठ विभाग

लैंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड बनाम अल्फ्रेड मैकएल्पाइन होम्स नॉर्थ लिमिटेड 19

हडसन के सूत्रों के सटीक होने की ओर इशारा करते हुए:

“इसके अलावा एम्डेन सूत्र, हडसन सूत्र के साथ सामान्य रूप से (बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पर हडसन देखें, (11 वां संस्करण, 1995) पैरा 8-182 एट सेक) और इसके अमेरिकी समकक्ष के साथ आइकले सूत्र, विभिन्न मान्यताओं पर निर्भर है जो हमेशा मौजूद नहीं होते हैं और जो, यदि मौजूद नहीं हैं, तो एक सूत्र के उपयोग को उचित नहीं ठहराएंगे। उदाहरण के लिए हडसन सूत्र यह स्पष्ट करता है कि बाधा का एक तत्व आवश्यक है (हडसन पैरा 8.185 देखें) अर्थात् लाभ के संबंध में, कि लाभ कहीं और अर्जित करने में सक्षम था और उसके बाद काम की लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले बाजार में कोई बदलाव नहीं हुआ था। यह भी स्थापित किया जाना चाहिए कि ठेकेदार कहीं और संसाधनों को तैनात करने में असमर्थ था और अन्य स्रोतों से अधिभार की लागत की वसूली की कोई संभावना नहीं थी, जैसे कि काम की बढ़ी हुई मात्रा से। इस प्रकार

19 (1995) 76 बीएलआर 59।

इस तरह के सूत्रों के केवल तभी मूल्यवान होने की संभावना है जब देरी का कारण बनने वाली घटना अनुबंध का उल्लंघन है (या इसकी विशेषताएँ हैं)।”

24. जैसा कि मैकडमॉट इंटरनेशनल इंक. में उल्लेख किया गया है, हडसन का 11 वां

संस्करण में आइकले सूत्र का उल्लेख किया गया है, जो अधिक सटीकता और सटीकता के साथ परिणामी फाइ ग्युर्स देता है। यह सूत्र, जो 1960-20 के दशक में उभरा था, कहीं अधिक सूक्ष्म और कठोर है, क्योंकि इसके लिए बिल्डर/ठेकेदार को अनुबंध अवधि के दौरान कुल अधिभार की गणना और मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। यह कुल अधिभार के आनुपातिक गुट को निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से विलंबित अनुबंध के साथ अनुबंध अवधि के दौरान ठेकेदार/बिल्डर के सभी अनुबंधों को ध्यान में रखता है। हालांकि, हडसन और आइकले दोनों के सूत्रों में, वसूल की जाने वाली राशि साप्ताहिक या मासिक रूप से निर्धारित की जाती है, जो अनुबंध पूरा होने में देरी से अर्जित होने की उम्मीद है।

25. हडसन के सूत्र के परिणामस्वरूप दोहरी वसूली हो सकती है क्योंकि प्रोफिटी में जोड़ा जा रहा प्रोफिटी पहले से ही 'अनुबंध राशि' के भीतर शामिल है। इस दोहरी वसूली को टालने के लिए, यह सुझाव दिया गया है कि सूत्र को 'कॉन्ट्रैक्ट सम लेस

ओवरहेड एंड प्रोफिट' में संशोधित किया जाना चाहिए।²¹ भिन्नताओं जैसे अतिरिक्त कार्यों के लिए वित्तीय खाते के मूल्य में किसी भी वृद्धि में ओवरहेड्स और प्रोफिट्स का अपना तत्व होता है। इसलिए, अन्य सूत्रों की तरह हडसन के सूत्र, जो केवल अवशोषित ओवरहेड के लागत प्रभाव के मोटे अनुमान हैं, को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण गणना सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी और सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए।²²

26. हडसन ने अपने 14 वें संस्करण में देरी की अवधि के दौरान प्रबंधन या अधिभार के दावे का उल्लेख किया है। लेखक ने हडसन के सूत्र के साथ-साथ आइकले के सूत्र का भी उल्लेख किया है और कहा है कि हडसन के दृष्टिकोण की हाल की सीमाओं पर अधिक जोर दिया गया है क्योंकि अंग्रेजी अदालतें समय प्रबंधन के लिए अपने दृष्टिकोण और दावों के मूल्यांकन में अधिक उदार हो गई हैं। लेखक जो ऊपर बताया गया है उसे स्वीकार करते हैं, और किसी भी दोहरी वसूली से बचने के लिए देरी के मामलों में ध्यान रखने की आवश्यकता, अन्य दावों के साथ ओवरलैप, या जब ठेकेदार द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाता है

20 इस सूत्र का नाम आर्म्ड सर्विसेज बोर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपीलस के फैसले से लिया गया है, जो कि एचले कॉर्पोरेशन मामले, एसबीसीए नंबर 5183,60-2 बीसीए में लिया गया है।

21 आइबीआई।

22 हेड ऑफिस सीई ओवरहेड्स के लिए दावे-सूत्रों के विकल्प, जॉन डब्ल्यू. पेटेट, 1999।

465

BATLIBOI पर्यावरण इंजीनियर लिमिटेड बनाम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड. [संजीव खन्ना, जे.] 466

परिवर्तन (ओं) के खाते, या उल्लंघन के लिए किसी भी नुकसान का अनुबंध मूल्य का उपयोग करके निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। "अनुचित खर्चों को जोड़कर "मोटा होना" स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि कुल लागत विधि में, कारण और प्रभाव को विश्वसनीय रूप से जोड़ने में भिन्नता है, हालांकि यह अधिक सटीक और तथ्यात्मक रूप से सटीक है। इस प्रकार, हडसन की विधि को सावधानी के साथ गणना के आधार के रूप में और एक अंतिम उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए, जहां नुकसान की गणना करने का कोई अन्य तरीका संभव या गणितीय रूप से सटीक नहीं है। हडसन की गणना में अशुद्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, और इसका हिसाब रखा जाना चाहिए और उन्हें बेअसर किया जाना चाहिए। जब हडसन का सूत्र लागू किया जाता है तो पूरी सावधानी और सावधानी के साथ होना चाहिए ताकि नुकसान को अधिक न दिया जा सके।

27. वर्तमान मामले में मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने इन सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू किया है, आवश्यक देखभाल और सावधानी की अनदेखी की है और नुकसान को पूरी तरह से और असामान्य रूप से बढ़ाने के लिए एकतरफा दृष्टिकोण अपनाया है। ऊपर पैराग्राफ 11 में उद्धृत निर्देश रुपये देने में अति-कथन और वृद्धि को दर्शाते हैं। 1,57,37,666/-, अधिभार के नुकसान और प्रोफिट्स/प्रोफिटेबिलिटी के नुकसान के लिए, रु. 5,74,35,212/-। रुपये. 1,21,95,859.68-अवधि के भीतर किए गए काम के लिए भुगतान किया गया था। रु. 2,92,07,619.13 को कार्यकाल के बाद किए गए काम के लिए भुगतान किया गया था। इस प्रकार, रु. 4,14,03,478.81-80 प्रतिशत काम के लिए भुगतान किया गया था। शेष राशि रु. 1,14,87,042.00 थी। ओवरहेड्स और प्रोफिट्स/प्रोफिटेबिलिटी के नुकसान के लिए दी जाने वाली राशि रु. 1,57,37,666/- है। हानि की गणना के लिए कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया है या इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। यहां तक कि अगर कोई बी. ई. ई. एल. द्वारा दिए गए चार्ट पर भरोसा करता है, और फाइंडिंग में विरोधाभासों को नजरअंदाज करता है, तो भी दी गई राशि अत्यधिक असमान और अत्यधिक है। यह स्पष्ट रूप से ओवरलैपिंग या कम से कम नुकसान/क्षति के आंशिक रूप से दोगुने होने का मामला है।

28. मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने स्वीकार किया है कि शमन का सिद्धांत लागू है लेकिन यह मानता है कि बी. ई. ई. एल. नुकसान को कम करने का एकमात्र तरीका रविवार या छुट्टियों पर काम करना था। यह तर्क फिर से प्रत्यक्ष रूप से गलत और गलत है। अतिरिक्त खर्चों के संबंध में शमन का सिद्धांत रविवार या छुट्टियों पर काम करना अनिवार्य नहीं करता है।

29. हम निष्क्रिय मशीनरी और उपकरणों के लिए दावा संख्या 2 का उल्लेख करना चाहेंगे। यह अनुबंध की विस्तारित अवधि के कारण था। Rs.84,00,000/- से अधिक के इस दावे को Rs.12,00,000/- के लिए केवल यह कहते हुए स्वीकार कर लिया गया है कि विद्वान मध्यस्थ ने स्थल का निरीक्षण किया था और उनकी राय में, दावे में सार है। स्थल का निरीक्षण किया गया था

अगस्त 1997 के बाद मध्यस्थ की नियुक्ति, जबकि बी. ई. ई. एल. ने एक साल से अधिक समय पहले मार्च 1996 में अनुबंध को छोड़ दिया था। राशि प्रदान करने के लिए कोई कारण और आधार बताए बिना यह राशि केवल इप्सी डिक्सिट पर दी जाती है।

30. ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत पुरस्कारों की समीक्षा करने की अदालत की शक्ति का दायरा और दायरा विवादास्पद रहा है।, 'भारत की सार्वजनिक नीति के साथ आई. सी. टी. में' अभिव्यक्ति की व्याख्या पर। विधायी हस्तक्षेप के साथ-साथ न्यायिक घोषणाएं भी हुई हैं। वर्तमान मामले के संदर्भ में, हमें प्रावधानों की व्याख्या करने की आवश्यकता है क्योंकि वे उस तारीख को मौजूद थे जिस दिन पुरस्कार पर आपत्तियां दर्ज की गई थीं, यानी 21.06.1999 पर। तदनुसार, 2016 के अधिनियम संख्या 3 के अनुसार ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 में पूर्वव्यापी प्रभाव वाले संशोधन और ए एंड सी अधिनियम की संशोधित धारा 34 की जांच करने वाले इस न्यायालय के निर्णयों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

31. पुरस्कार के बाद हस्तक्षेप और ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत अदालतों द्वारा दूसरी नजर का विस्तार बारहमासी बातचीत का विषय रहा है। मध्यस्थता की नींव पक्ष की स्वायत्तता है। दोनों को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपने विवादों/दावों को निपटाने के लिए एक समझौता करने की स्वतंत्रता है, जिसका निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी है।²³ यह तर्क दिया जाता है कि मध्यस्थता का उद्देश्य अदालत के निर्णय के विकल्प के रूप में त्वरित और त्वरित एकतरफा निर्णय है, और इसलिए, अदालतों द्वारा निर्णय के बाद का हस्तक्षेप अनुचित है, और एक अभिशाप है जो मध्यस्थता की मौलिक संरचना को कमजोर करता है, जो किसी पक्ष के अधिकार से सहमति और स्वैच्छिक विचलन है ताकि न्यायपालिका द्वारा अपने दावे या विवाद का निर्णय लिया जा सके। प्रक्रिया अनौपचारिक है, और वैध होने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, यह तर्क दिया जाता है कि पक्ष की स्वायत्तता को एक पूर्ण बचाव के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि एक पक्ष के रूप में विवादों/दावों को सहमति से एक निजी न्यायाधिकरण को भेजने के लिए सहमत होने के बावजूद, विवादों के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाधान के लिए संवैधानिक और बुनियादी मानव अधिकार को दूर नहीं करता है। न्यायालय को अपनी शक्तियों का प्रयोग तब करना चाहिए जब निर्णय अनुचित, मनमाना, विकृत या अन्यथा अनुचित हो।

23 विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और अन्य, (2021) 2 देखें।

एस. सी. सी. 1, जो विषय मामलों और दावों की मध्यस्थता और गैर-मध्यस्थता की जांच करता है, इस मामले में किस पहलू की जांच नहीं की जाएगी।

24 अभिव्यक्ति "न्यायिक रूप से", औपचारिक/अदालती कार्यवाही के साथ मध्यस्थता की बराबरी नहीं करती है, और इसमें एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय शामिल होगा।

467

BATLIBOI पर्यावरण इंजीनियर लिमिटेड बनाम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. [संजीव खन्ना, जे.] 468 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

कानून। जबकि मध्यस्थता विवाद समाधान का एक निजी रूप है, मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन को 'न्यायिक रूप से' ठोस और वस्तुनिष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए उचित प्रक्रिया और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और तर्कसंगतता की न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। यदि ये आवश्यकताएँ, जो मध्यस्थता सहित सभी प्रकार के निर्णयों के लिए समान रूप से मौलिक हैं, मध्यस्थता कार्यवाही में पर्याप्त रूप से समायोजित नहीं हैं और परिणाम बाधित है, तो पुरस्कार को अदालत द्वारा हस्तक्षेप को आमंत्रित करना चाहिए।

32. प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों को अलग करने और संतुलित करने के लिए, जब एक या दोनों पक्षों द्वारा किसी निर्णय को चुनौती दी जाती है तो अदालतों के हस्तक्षेप की डिग्री और दायरे को बताए जाने की आवश्यकता होती है। कानून के बयान के रूप में सुलह और विशेष रूप से किसी विशेष मामले में आवेदन एक आसान अभ्यास नहीं रहा है। हम ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत अदालतों द्वारा निर्णय के बाद के हस्तक्षेप की चौड़ाई और दायरे की व्याख्या करने में इस अदालत द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का उल्लेख करते हुए शुरू करते हैं।

33. ए एंड सी अधिनियम की धारा 34, 2016 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा किए गए संशोधन से पहले, 23.10.2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, निम्नानुसार है:

“34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन।—(1) माध्यस्थम् अधिनिर्णय के विरुद्ध न्यायालय का सहारा केवल उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन द्वारा लिया जा सकता है।

(2) एक मध्यस्थता पुरस्कार को अदालत द्वारा केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब-(ए) आवेदन करने वाला पक्ष इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि-(आई) एक पक्ष कुछ अक्षमता में था; या

((ii) मध्यस्थता समझौता उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके अधीन पक्षों ने इसे किया है या उस पर कोई संकेत देने में विफल रहने पर, उस समय लागू कानून के तहत; या

((ग) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह अपना मामला पेश करने में असमर्थ था; या

((iv) मध्यस्थता पुरस्कार एक ऐसे विवाद से संबंधित है जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आता है या नहीं आता है, या इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल हैं:

बशर्ते कि, यदि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णयों को उन लोगों से अलग किया जा सकता है जो इस तरह से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो केवल मध्यस्थता पुरस्कार का वह हिस्सा जिसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं, को अलग किया जा सकता है; या

(v) मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना पक्षकारों के समझौते के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा समझौता इस भाग के किसी प्रावधान के साथ नहीं था जिससे पक्षकार अवमूल्यन नहीं कर सकते, या ऐसे समझौते में विफल रहना, इस भाग के अनुसार नहीं था; या

(ख) न्यायालय का कहना है कि -

((i) विवाद का विषय उस समय लागू कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है, या

((ii) मध्यस्थता निर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के अनुरूप है।स्पष्टीकरण.—उपखंड (ii) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कोई पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ मिश्रित है यदि पुरस्कार देना धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित था या लगाया गया था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन था।

(3) अलग रखने के लिए आवेदन उस तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है जिस दिन वह आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ था या, यदि धारा 33 के तहत अनुरोध किया गया था, उस तारीख से जिस दिन मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा उस अनुरोध का निपटारा किया गया था:

बशर्ते कि यदि न्यायालय को संतुष्ट किया जाता है कि आवेदक को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं।

(4) उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायालय, जहां यह उचित हो और किसी पक्ष द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाए, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही को फिर से शुरू करने का अवसर देने के लिए अपने द्वारा निर्धारित समय की अवधि के लिए कार्यवाही को स्थगित कर सकता है या ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण की राय में मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के आधार को समाप्त कर देगा।”

34. ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के लिए आवश्यक है कि मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अदालत का सहारा एक पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए जो धारा 34 की उप-धारा (2) और (3) के अनुसार किसी पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन करता है। ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2) में सात आधार निर्धारित किए गए हैं जिन पर एक अदालत मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द कर सकती है। उप-धारा (2) में दो खंड हैं, (ए) और (बी)। खंड (ख) में दो उपखंड होते हैं, अर्थात् उपखंड (i) जिसमें कहा गया है कि जब विवाद का विषय कुछ समय के लिए लागू कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है, और उपखंड (ii), जिसमें कहा गया है कि अदालत एक मध्यस्थ पुरस्कार को अलग कर सकती है जब पुरस्कार 'भारत की सार्वजनिक नीति के साथ मिश्रित' हो। हम बाद में इस न्यायालय के 'भारत की सार्वजनिक नीति के साथ आई. सी. टी. की व्याख्या करने वाले निर्णयों और स्पष्टीकरण की जांच करेंगे।

35. ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (ए) से उप-धारा (2) के तहत, एक अदालत उप-खंड (i) से (v) के आधार पर एक पुरस्कार को अलग कर सकती है, अर्थात् जब कोई पक्ष कुछ असमर्थता के तहत होता है; मध्यस्थता समझौता उस समय लागू कानून के तहत मान्य नहीं है; जब धारा 34 के तहत आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी जाती है, या वह अपना मामला पेश करने में असमर्थ होता है; और जब मध्यस्थता न्यायाधिकरण या मध्यस्थता प्रक्रिया की संरचना पक्षों के बीच समझौते के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा समझौता अनिवार्य और बाध्यकारी गैर-विवादास्पद प्रावधान के साथ नहीं था, या था। उपखंड (iv) में कहा गया है कि मध्यस्थता पुरस्कार को तब अलग किया जा सकता है जब वह किसी ऐसे विवाद से संबंधित हो जिस पर विचार नहीं किया गया हो, या जो मध्यस्थता प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आता हो, या इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल हो। हालांकि, परंतुक में कहा गया है कि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों में निर्णय को प्रस्तुत नहीं किए गए लोगों से अलग किया जा सकता है, फिर मध्यस्थता पुरस्कार के उस हिस्से को जिसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए मामले पर निर्णय शामिल है, अलग किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, हमें ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के खंड (ए) से उप-धारा (2) के उप-खंडों की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, इस निर्णय को किसी भी अवलोकन के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, यहां तक कि उक्त खंडों पर आज्ञाकारी आदेश के रूप में भी।

36. ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 (2) के उपखंड (2) से खंड (बी) के लिए स्पष्टीकरण, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है और 2016 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पहले, संदेह से बचने के लिए अभिनिर्धारित और घोषित किया गया था कि एक पुरस्कार 'में' है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

भारत की सार्वजनिक नीति के साथ आई. सी. टी. का टकराव, यदि पुरस्कार देने के लिए धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रेरित किया गया है, या ए एंड सी अधिनियम की धारा 75 या 81 का उल्लंघन किया गया है। ए एंड सी अधिनियम की धारा 75 और 81 दोनों ए एंड सी अधिनियम के भाग III के तहत आती हैं, जो सुलह की कार्यवाही से संबंधित हैं। ए एंड सी अधिनियम की धारा 75 निपटान कार्यवाही की विश्वसनीयता से संबंधित है और धारा 81 सुलह कार्यवाही में साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित है। इस स्तर पर यह ध्यान देने योग्य है कि 'सार्वजनिक नीति' के तहत 'धोखाधड़ी' और 'भ्रष्टाचार' दो विशिष्ट आधार हैं, लेकिन ये एकमात्र और एकमात्र आधार नहीं हैं जिन पर 'सार्वजनिक नीति' के आधार पर एक पुरस्कार अलग किया जा सकता है।

37. 2016 के अधिनियम संख्या 3 ने 23.10.2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव ect के साथ ऊपर उल्लिखित स्पष्टीकरण को दो नए स्पष्टीकरणों द्वारा प्रतिस्थापित किया है जो अलग-अलग शब्दों में हैं। 25 ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2-ए), जिसे 2016 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा 23.10.2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ स्थापित किया गया था, में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं के अलावा अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न होने वाले मध्यस्थता पुरस्कार को अदालत द्वारा रद्द किया जा सकता है, यदि यह पुरस्कार के सामने दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता से दूषित है। ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2-ए) के परंतुक में यह भी कहा गया है कि पुरस्कार को केवल कानून के गलत अनुप्रयोग या साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर अलग नहीं किया जाएगा। उपरोक्त उप-धारा की वर्तमान मामले के तथ्यों में जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है।

25 2016 के अधिनियम सं. 3 द्वारा प्रतिस्थापित ए एंड सी अधिनियम के उपखंड (ii) से खंड (ख) से धारा 34 (2) के स्पष्टीकरण 1 और 2 निम्नानुसार हैं:

स्पष्टीकरण 1.—किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ जुड़ा हुआ है, केवल तभी जब -

(i) पुरस्कार देने के लिए धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार को प्रेरित किया गया था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन किया गया था; या

((ii) यह भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन है; या (iii) यह नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ मिला हुआ है।

स्पष्टीकरण 2.—संदेह से बचने के लिए, यह परीक्षण कि क्या भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन हुआ है, विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा नहीं करेगा।

2016 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा अंतःस्थापित ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 (2) की उप-धारा 2 ए निम्नानुसार है:

(2-ए) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं के अलावा अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न होने वाले मध्यस्थता पुरस्कार को भी अदालत द्वारा दरकिनार किया जा सकता है, यदि अदालत यह मानती है कि पुरस्कार के सामने पेटेंट अवैधता दिखाई देने से पुरस्कार दूषित हो गया है:

बशर्ते कि कोई पुरस्कार केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के आधार पर या साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन द्वारा अलग नहीं किया जाएगा।

471

BATLIBOI पर्यावरण इंजीनियर लिमिटेड बनाम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड. [संजीव खन्ना, जे.] 472

वर्तमान मामले में ए एंड सी अधिनियम के उपखंड (बी) से 34 (2) के लिए (ii) प्रतिस्थापित स्पष्टीकरणों की व्याख्या करें और उन्हें लागू करें।

38. ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत 'सार्वजनिक नीति' अभिव्यक्ति व्यापक और संकीर्ण दोनों व्याख्या करने में सक्षम है। एक व्यापक व्याख्या लेते हुए, ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड में यह न्यायालय।v. सॉ पाइप्स लिमिटेड।, 26 अभिनिर्धारित किया कि विधायी इरादा किसी पुरस्कार को बनाए रखना नहीं था यदि यह किसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह न्याय की मूल अवधारणा के विपरीत होगा। 'सार्वजनिक नीति' की अवधारणा एक ऐसे मामले को दर्शाती है जो सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित से संबंधित है। एक पुरस्कार जो स्पष्ट रूप से वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे जनहित में नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे और विस्तार का विस्तार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक पुरस्कार को अलग किया जा सकता है यदि यह इसके विपरीत है: (क) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या

((ख) भारत का हित; या

((ग) न्याय या नैतिकता, या

(घ) इसके अलावा, यदि यह स्पष्ट रूप से अवैध है।

फिर भी, निर्णय में कहा गया है कि विवादित प्रश्न पर निष्कर्ष पर पहुंचने में केवल तथ्य या कानून की त्रुटि अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र नहीं देगी। हालाँकि, यह तीन पहलुओं पर निर्भर करेगा: (क) क्या संविदात्मक विवाद का निर्णय करने के लिए सामान्य शब्दों में निर्देश दिया गया था, जिस मामले में पुरस्कार को अलग किया जा सकता है यदि पुरस्कार गलत कानूनी स्थिति पर आधारित है; (ख) यह प्रस्ताव एक तर्कपूर्ण पुरस्कार के मामले में भी अच्छा होगा, जो कानून के कानूनी प्रस्ताव और/या इसके आवेदन पर गलत है; और (ग) जहां कानून का एक विशिष्ट सी प्रश्न एक मध्यस्थ को प्रस्तुत किया जाता है, कानून के बिंदु पर गलत निर्णय पुरस्कार को बुरा नहीं बनाता है, जब तक कि अदालत को संतुष्ट नहीं किया जाता है कि मध्यस्थ ने अवैध रूप से कार्रवाई की थी। उक्त मामले में, अदालत ने इस आधार पर पुरस्कार को रद्द कर दिया कि पुरस्कार ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अनुबंध की शर्तों पर विचार नहीं किया था कि क्या हजनि का दावा करने वाला पक्ष उसी का हकदार है। अनुबंध अधिनियम की धारा 73 और 74 के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया था, जो परिसमापन क्षति, सामान्य क्षति और दंड की शर्तों से संबंधित हैं। यह दृष्टिकोण लंबे समय तक कायम रहा था और था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के बाद के निर्णयों में लागू किया गया।

मित्रों, कोल कार्बनाइजेशन 27, सेंट्रोटेड मिनरल्स एंड मेटल्स इंक. बनाम. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 28, दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम आर. एस. शर्मा एंड कंपनी 29, जे. जी. इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य 30, और भारत संघ बनाम एल. एस. एन. मूर्ति। 31

39. 2006 में, मैकडर्मॉट इंटरनेशनल इंक. में इस अदालत ने इसके बावजूद

सॉ पाइप्स लिमिटेड के अनुपात का पालन करते हुए, पुरस्कार के बाद के हस्तक्षेप में अदालतों की प्रतिबंधात्मक भूमिका के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियां कीं। रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 32 में पेश किए गए तीन आधारों के अलावा, जैसा कि ऊपर देखा गया है, सॉ पाइप्स लिमिटेड को 'पेटेंट अवैधता' का एक अतिरिक्त आधार पेश किया गया था, ताकि एक मध्यस्थ पुरस्कार को अलग करने में अदालत के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सके। मैकडर्मॉट इंटरनेशनल इंक. में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पेटेंट अवैधता ऐसी होनी चाहिए जो मामले की जड़ तक जाए। सार्वजनिक नीति का उल्लंघन इतना अनुचित और अनुचित होना चाहिए कि अदालत की अंतरात्मा को झटका लगे। जहां मध्यस्थ अनुबंध के स्पष्ट कानून के विपरीत या उससे परे कार्य करता है या राहत देता है, ऐसे पुरस्कार ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के दायरे में आते हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक नीति क्या होगी, यह लेन-देन की प्रकृति और कानून पर निर्भर करता है। पक्ष की दलीलें और अदालत के समक्ष लाई गई सामग्री अदालत को यह निर्णय करने में सक्षम बनाने के लिए प्रासंगिक होगी कि सार्वजनिक भलाई या सार्वजनिक हित में क्या है, या जो अन्यथा किसी प्रासंगिक बिंदु पर सार्वजनिक भलाई और हित के लिए हानिकारक होगा। इसलिए, इसे किसी विशेष सरकार की सार्वजनिक नीति से अलग किया जाना चाहिए।

40. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था। दीवान चंद राम सरन 33 ने इस स्पष्टीकरण के साथ कि जहां अनुबंध की एक अवधि दो व्याख्याओं में सक्षम है और मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय है, यह नहीं कहा जा सकता है कि मध्यस्थ ने अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा की या मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अनुबंध की शर्तों के खिलाफ है। न्यायालय पुरस्कार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और इसके स्थान पर इसे प्रतिस्थापित कर सकता है।

27 (2006) 4 एससीसी 445। 28 (2006) 11 एससीसी 245। 29 (2008) 13 एससीसी 80। 30 (2011) 5 एससीसी 758। 31 (2012) 1 एससीसी 718।

32 1994 पूरक (1) एस. सी. सी. 644। 33 (2012) 5 एस. सी. सी. 303।

473

BATLIBOI पर्यावरण इंजीनियर लिमिटेड बनाम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. [संजीव खन्ना, जे.] 474

मध्यस्थ द्वारा स्वीकार किए गए निर्णय और व्याख्या को देखते हुए, इसका कारण यह है कि न्यायालय ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय मध्यस्थ के निर्णय और निर्णय पर अपील में नहीं बैठता है। मध्यस्थ वैध रूप से अपने सामने रखी गई सामग्री पर विचार करने और समझौते की व्याख्या करने का हकदार है। निर्णय को अनिवार्य और बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

41. इसके बाद, ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम. वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल

लिमिटेड, 34 इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सॉ पाइप्स लिमिटेड में न्यायालय ने इस बात की जांच नहीं की कि 'भारतीय कानून की मौलिक नीति' क्या होगी। इस न्यायालय की राय में 'भारतीय कानून की मौलिक नीति' अभिव्यक्ति में इस देश में न्याय के प्रशासन और कानून के प्रवर्तन के लिए आधार प्रदान करने वाले सभी मौलिक सिद्धांत शामिल

हैं।तीन विशिष्ट और मौलिक न्यायिक सिद्धांत थे जो 'भारतीय कानून की मौलिक नीति' का एक अभिन्न अंग हैं।पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि अदालत या प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक निर्धारण में जो किसी नागरिक के अधिकारों को प्रभावित करता है या नागरिक परिणामों की ओर ले जाता है, अदालत या प्राधिकरण को न्यायिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।न्यायिक दृष्टिकोण के प्रति निष्ठा का अर्थ है कि न्यायालय या प्राधिकरण को मनमाने, मनमौजी या सनकी तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए।न्यायालय या प्राधिकरण को एक प्रामाणिक तरीके से कार्य करना चाहिए और विषय के साथ निष्पक्ष, उचित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए।निर्णय बाहरी विचारों से प्रेरित नहीं होना चाहिए।दूसरा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।इसमें यह आवश्यकता शामिल होगी कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को किसी न किसी तरह से दृष्टिकोण लेते हुए उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर अपना दिमाग लगाना चाहिए।दिमाग का गैर-अनुप्रयोग एक दोष है जो किसी भी निर्णय के लिए घातक है।निर्णय के समर्थन में कारणों को दर्ज करके दिमाग का उपयोग सबसे अच्छा किया जाता है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, ए एंड सी 35 की धारा 31 (3) (ए) में कहा गया है कि मध्यस्थता पुरस्कार उन कारणों को बताएगा जिन पर यह आधारित है, जब तक कि पक्ष इस बात पर सहमत न हों कि कोई कारण नहीं दिया जाना है।धारा 34 (2) के उपखंड (i) और (iii) भी प्राकृतिक न्याय के विभिन्न पहलुओं को संदर्भित करते हैं।किसी दिए गए मामले में धारा 34 (2) का उपखंड और धारा 34 (2) के खंड (बी) का उपखंड समान रूप से लागू हो सकता है।अंत में, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निर्णय विकृत न हो 34 (2014) 9 एस. सी. सी. 263, (संक्षेप में, पश्चिमी गेको) 35 सुप्रा फुटनोट 5।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

या यह तर्कहीन है कि कोई भी उचित व्यक्ति इस पर नहीं पहुंचा होगा या उसे अदालत में कायम नहीं रखा जाएगा।किसी निर्णय की विकृति या तर्कहीनता का परीक्षण वेड्सबरी के तर्कसंगतता के सिद्धांत 36 के आधार पर किया जाता है।साथ ही, यह आगाह किया गया कि यह न्यायालय 'भारतीय कानून की मौलिक नीति' का गठन करने के लिए एक विस्तृत गणना का प्रयास नहीं कर रहा है, क्योंकि एक सीधी अवज्ञा संभव नहीं है।यदि उनके समक्ष साबित किए गए तथ्यों पर, मध्यस्थ एक निष्कर्ष निकालने में विफल रहते हैं जो तैयार किया जाना चाहिए था या यदि उन्होंने एक ऐसा निष्कर्ष निकाला है जो इसके बावजूद, अन्याय के परिणामस्वरूप असमर्थनीय है, तो एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किए गए निर्णय को चुनौती दी जा सकती है जो काफी अक्षांश का आनंद लेता है और पुरस्कार देने में संयुक्त रूप से खेलता है।

42. एसोसिएट बिल्डर्स में इस न्यायालय के निर्णय ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ में सार्वजनिक नीति के प्रश्न की विस्तृत रूप से जांच की, विशेष रूप से 'भारतीय कानून की मौलिक नीति' शीर्षक के तहत।यह पहली बार माना गया था कि न्यायिक दृष्टिकोण का सिद्धांत निर्णय को निष्पक्ष, उचित और उद्देश्यपूर्ण होने की मांग करता है।विपरीत दिशा में, मनमाना और सनकी कुछ भी उक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा।

43. पश्चिमी गेको में तीसरे सिद्धांत का उल्लेख करते हुए, यह समझाया गया था कि निर्णय अतार्किक और विकृत होगा यदि (ए) यह बिना किसी साक्ष्य के आधारित है; (बी) यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण उस निर्णय के लिए कुछ अप्रासंगिकता को ध्यान में रखता है जिस पर वह आता है; या (सी) अपने निर्णय पर पहुंचने में महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करता है।उत्पाद शुल्क और कराधान कार्यालय में निर्धारित मानक -

सह-निर्धारण प्राधिकरण बनाम गोपी नाथ एंड संस 37 और कुलदिप सिंह बनाम

पुलिस आयुक्त 38 को विकृति के अच्छे कार्य परीक्षण के रूप में लागू किया जाना चाहिए और उन पर भरोसा किया जाना चाहिए।गोपी नाथ एंड संस में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उन मामलों के अलावा जहां प्रासंगिक सामग्रियों की अनदेखी या उन्हें बाहर करके या अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए तथ्य का निष्कर्ष निकाला जाता है, यह निर्णय विकृत और असंवैधानिक है जब यह तर्क की घोर अवहेलना करता है कि यह अतार्किकता का दोष है।कुलदिप सिंह ने स्पष्ट किया है कि जब कोई साक्ष्य या साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय होता है और कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो यह गलत है।अगर कोई सबूत है जो

36 जैसा कि एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड के मामले में स्पष्ट किया गया है।वेड्सबरी

निगम।, (1948) 1 के बी 223:(1947) 2 सभी ईआर 680 (सीए)।37 1992 पूरक (2) एस. सी. सी. 312, (संक्षेप में, गोपी नाथ एंड संस)।38 (1999) 2 एससीसी 10.

कार्रवाई की जा सकती है और उस पर भरोसा किया जा सकता है, यह कितना भी व्यापक क्यों न हो, निष्कर्ष को विकृत नहीं माना जाना चाहिए। एसोसिएट बिल्डर्स में इस अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक मध्यस्थता पुरस्कार के लिए सार्वजनिक नीति परीक्षण अदालत को अपील की अदालत के रूप में कार्य करने का अधिकार क्षेत्र नहीं देता है और इसके परिणामस्वरूप तथ्य की त्रुटियों को ठीक नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण साक्ष्य की गुणवत्ता और मात्रा का अंतिम मास्टर है। कम सबूत या बिना सबूत के आधार पर एक पुरस्कार, जो एक प्रशिक्षित कानूनी दिमाग के लिए गुणवत्ता में माप नहीं करता है, इस स्कोर पर अमान्य नहीं माना जाएगा। प्रत्येक मध्यस्थ के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्यायाधीश के रूप में कानून में प्रशिक्षित व्यक्ति हो। कभी-कभी, निर्णय समानता पर कार्य करते हुए लिए जाते हैं और ऐसे निर्णय न्यायसंगत और निष्पक्ष हो सकते हैं जिन्हें ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत इस आधार पर पलट नहीं दिया जाना चाहिए कि मध्यस्थ का दृष्टिकोण मनमाना या मनमौजी था। सार्वजनिक नीति, न्याय या नैतिकता के तीसरे आधार का उल्लेख करते हुए, यह देखा गया है कि ये दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। एक पुरस्कार न्याय के खिलाफ होता है जब यह अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है, जैसा कि एक उदाहरण में जहाँ दावेदार ने अपने दावे को प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने न्याय के किसी भी उचित आधार के बिना अधिक राशि का फैसला सुनाया है। नैतिकता अनिवार्य रूप से उन समझौतों को शामिल करेगी जो अवैध हैं और उन समझौतों को भी जिन्हें दिन के प्रचलित रूढ़ियों को देखते हुए लागू नहीं किया जा सकता है। यहाँ फिर से हस्तक्षेप केवल तभी होगा जब कुछ अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दे। इसके अलावा, 'पेटेंट अवैधता' तीन उप-शीर्षों को संदर्भित करता है: (क) भारत के मूल कानून का उल्लंघन, जिसे इस तरह से प्रतिबंधित और सीमित किया जाना चाहिए कि अवैधता मामले की जड़ तक जाए और तुच्छ प्रकृति की न हो। इस संबंध में ए एंड सी अधिनियम की धारा 28 (1) के खंड (ए) का संदर्भ दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि भाग I के तहत मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत विवाद उस समय लागू मूल कानून के अनुसार होगा। दूसरा उप-शीर्ष तब होगा जब मध्यस्थ ए एंड सी अधिनियम की धारा 31 (3) के उल्लंघन में निर्णय में कोई कारण नहीं बताएगा। तीसरा उप-शीर्ष ए एंड सी अधिनियम की धारा 28 (3) के उल्लंघन से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी मामलों का फैसला करेगा और लेनदेन पर लागू व्यापार के उपयोग को ध्यान में रखेगा। इस अंतिम उप-शीर्ष को इस चेतावनी के साथ समझा जाना चाहिए कि मध्यस्थ को अनुबंध की शर्तों को उचित तरीके से समझने और व्याख्या करने का अधिकार है। इस तरह की व्याख्या पुरस्कार को अलग करने का आधार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनुबंध की शर्तों का निर्माण निश्चित रूप से मध्यस्थ को तय करना है। पुरस्कार को इस उप-शीर्ष के तहत केवल तभी अलग रखा जा सकता है जब मध्यस्थ पुरस्कार को इस तरह से समझता है कि कोई भी निष्पक्ष या उचित व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

44. जैसा कि पहले देखा गया है, हमें 2016 के अधिनियम संख्या 3 के अनुसार ए एंड सी अधिनियम में किए गए संशोधन और ए एंड सी अधिनियम की संशोधित धारा 34 से संबंधित निर्णयों की पूर्वव्यापी प्रभाव से जांच करने की आवश्यकता नहीं है। उल्लेखनीय है कि भारत के विधि आयोग द्वारा फरवरी 2015 में प्रकाशित 'सार्वजनिक नीति-रिपोर्ट संख्या 246 के बाद के विकास' शीर्षक से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन पर रिपोर्ट संख्या 246 की पूरक रिपोर्ट की टिप्पणियों के अनुसार ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 में संशोधन किया गया था। इस पूरक रिपोर्ट में कहा गया है कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत गुण-दोष के आधार पर मध्यस्थता पुरस्कार की समीक्षा करने की शक्ति, जैसा कि पश्चिमी जीको के मामले में स्पष्ट किया गया है, बाद में एसोसिएट बिल्डर्स में इसका पालन किया गया, ए एंड सी अधिनियम के उद्देश्य और न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के विपरीत है। एम. एम. टी. सी. लिमिटेड का संदर्भ भी आसानी से दिया जा सकता है। वेदांत लिमिटेड, 39

और सांगयोंग एंग। & कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग

भारतीय प्राधिकरण 40, जो 2016 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा संशोधित ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत अदालतों के हस्तक्षेप के दायरे की जांच करता है। एम. एम. टी. सी. लिमिटेड और सांगयोंग एंग।, और अन्य निर्णय जो ए एंड सी अधिनियम की संशोधित धारा 34 से संबंधित हैं जो वर्तमान मामले में लागू नहीं हैं। 45. हमने पुरस्कार, इसके पेटेंट और उससे

उत्पन्न होने वाली अवैधताओं का व्यापक रूप से विश्लेषण किया है, जैसे कि निष्कर्ष पर पहुंचने में तर्क की स्पष्ट कमी और प्रदान की गई राशि की गणना, जो वास्तव में, विरोधाभासी होने के अलावा, दोगुना या आंशिक रूप से दोगुना भुगतान के बराबर है। हमारे उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखते हुए, पुरस्कार को उचित रूप से अस्थिर माना गया है और ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के साथ पठित धारा 37 के तहत शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अलग कर दिया गया है।

46. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिका खारिज की जाती है।

निधि जैन

39 (2019) 4 एससीसी 163 (संक्षेप में, एम. एम. टी. सी. लिमिटेड)। 40 (2019) 15 एस. सी. सी. 131 (संक्षेप में, सांगर्योग एंग)।